

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 10 | अंक : 228 | गुवाहाटी | रविवार, 17 मार्च, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

असम भाजपा ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया **पेज 2**नरेंद्र मोदी को सभी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं : बीटीसी प्रमुख **पेज 3**लोकसभा 2024 के चुनाव में वाराणसी सबसे हाई प्रोफाइल सीट, पीएम... **पेज 5**स्पोर्ट्स को 6-1 से रॉड लिवरपूल क्वार्टर फाइनल में **पेज 7**

19 अप्रैल से एक जून तक सात चरणों में होंगे लोस चुनाव, चार जून को नतीजे

नई दिल्ली (हि.स.)। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की शनिवार को घोषणा कर दी। लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे। मतगणना चार जून को होगी और नतीजे भी उसी दिन दोपहर तक आ जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में पत्रकारों के दौरान चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। इस बार 22 राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में दो चरणों, छत्तीसगढ़ और असम में तीन चरणों, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में चार चरणों। महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में पांच चरणों में और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में सात चरणों में मतदान होगा। मणिपुर को एक सीट पर दो चरणों में मतदान होगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। देशभर में 543 लोकसभा सीटें हैं। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 412, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में अरुणाचल प्रदेश की सभी दो, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की एक, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की दो, मेघालय की सभी दो, मिजोरम की एकमात्र, नगालैंड की एक, राजस्थान की 12, सिक्किम की एक, तमिलनाडु की सभी 39, त्रिपुरा की एक, उत्तर प्रदेश की आठ, उत्तराखंड की सभी पांच, पश्चिम बंगाल की तीन, अंडमान निकोबार की एक, जम्मू-कश्मीर की एक, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की एक-एक सीट पर मतदान होगा। इस चरण में अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। नामांकन 27 मार्च तक किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 23 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। इस दौरान असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की तीन, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की एक, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की एक, उत्तर प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की तीन, जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर मतदान होगा। इस चरण में अधिसूचना 28 मार्च, नामांकन 4 अप्रैल, जांच 5 अप्रैल, नाम वापसी 8 अप्रैल को होगी। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों

लोकसभा चुनाव 2024		
पहला चरण 19 अप्रैल	दूसरा चरण 26 अप्रैल	तीसरा चरण 07 मई
चौथा चरण 13 मई	पांचवां चरण 20 मई	छठा चरण 25 मई
सातवां चरण 01 जून	मतगणना - 04 जून	

देशभर में लागू हुई आचार संहिता

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में आचार संहिता भी लागू हो गई है। लोकसभा की 543 सीटों के साथ ही 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। लोकसभा के चुनाव सात चरणों में होंगे। 22



राज्यों में एक चरण में चुनाव प्रस्तावित हैं। जबकि, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव कराने का

55 लाख ईवीएम का होगा इस्तेमाल : सीईसी

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि 97 करोड़ से अधिक मतदाता लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं और सभी को लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान संवाददाता

पूर्वोत्तर के सात राज्यों में तीन चरणों में होंगे मतदान

गुवाहाटी (हि.स.)। पूर्वोत्तर के सात राज्यों में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने आज देश के आम चुनाव के तारीखों की घोषणा की। चुनाव आयोग ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में देश में आम चुनाव की तारीख का एलान किया। 2024 का लोकसभा चुनाव सात चरणों में होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां असम में तीन चरणों में मतदान संपन्न होंगे। वहीं, मणिपुर और त्रिपुरा में दो-दो चरणों एवं शेष चार राज्यों में एक-एक चरणों में मतदान संपन्न होंगे। बहाग बिहू के बाद असम में आम चुनाव होंगे। असम में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। राज्य में मतदान 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को होगा।

मणिपुर : राहत शिविरों में रहने वालों को वहीं से मतदान की अनुमति मिलेगी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। साथ ही चुनाव आयोग ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के शिविरों में रहे लोगों के लिए खास इंतजाम किए जाने की जानकारी भी दी। चुनाव आयोग ने बताया कि लोकसभा चुनाव में शिविरों से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपुर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि हम सभी व्यवस्थाएं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक योजना बनाई है, जिसे हमने अधिसूचित कर दिया है... ताकि शिविर में मतदाताओं को शिविर से मतदान करने की अनुमति मिल सके। जैसे जम्मू-कश्मीर प्रवासियों के लिए एक योजना है... उसी तरह यह योजना मणिपुर में लागू होगी। मतदाताओं को संबंधित शिविरों से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। मणिपुर की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि चार जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे।

पूर्वाञ्चल केशरी
(असमिया दैनिक)
PURVANCHAL KESARI
(ASSAMESE DAILY)
GOOD LUCK PUBLICATIONS
House No. 30, D. Neog Path,
ABC, Guwahati - 781005
Mob: 94350 14771, 97070 14771

S.S. Traders
Suppliers in: All kinds of Door
Fittings Modular Kitchen
& Accessories, etc.
D. Neog Path,
Near Dona Planet
ABC, G.S. Road,
Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात
राज्य का आधार अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी
केंद्र ने सीएए के तहत आवेदन के लिए शुरू किया मोबाइल एप

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक मोबाइल एप शुरू किया, जो सीएए के तहत आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, एप को गूगल प्ले स्टोर या केंद्र सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून- 2019 के तहत आवेदन करने के लिए सीएए-2019 मोबाइल एप शुरू किया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र लोगों के लिए पोर्टल शुरू किया था।

लोस चुनाव : 85 साल से अधिक उम्र वाले लोग घर बैठे दे सकेंगे वोट

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों और चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से वोट सुविधाओं की घोषणा की। यह पहली बार है कि चुनाव निकाय घर से वोट की सुविधा प्रदान कर रहा है। आयोग ने विकलांग लोगों और उन लोगों के लिए भी कई प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की, जिन्हें सुलभ और समावेशी मतदान सुनिश्चित करने



की सुविधा प्रदान कर रहा है। आयोग ने विकलांग लोगों और उन लोगों के लिए भी कई प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की, जिन्हें सुलभ और समावेशी मतदान सुनिश्चित करने

के लिए सहायता की आवश्यकता है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40 प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक और क्वीलचेयर तैनात रहेंगे। विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप। स्कूलों में

यही समय है और सही समय है : पीएम

नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। इस बार पूरे देश में लोकसभा का चुनाव सात चरणों में कराए जाएंगे। वहीं, चुनाव की तारीखों के एलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) - एनडीए आम चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के एलान के बाद कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल से मतदान के पहले चरण का



शुरुआत होगा, जो सात चरणों तक चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता-जनार्दन के बीच जाएंगे।

मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। अपने तीसरे कार्यकाल में हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। हमारे बीते 10 साल उस गहरी खाई को भरने में भी बीते हैं, जो दशकों तक शासन करने वालों ने बनाई थी। इन 10 वर्षों में देशवासियों में ये आत्मविश्वास आया है कि हमारा भारत समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारा आगला कार्यकाल इन संकल्पों की सिद्धि की राह प्रशस्त करेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान आई.एन.डी.आई. गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 साल

रेवाड़ी में बड़ा हादसा स्पेयर पार्ट्स की कंपनी में फटा बॉयलर, 60 से ज्यादा लोग झुलसे

रेवाड़ी (हरियाणा)। हरियाणा के रेवाड़ी के धाकहेड़ा के हाउसिंग बोर्ड इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के डस्ट कलेक्टर में बॉयलर फट गया। इस दौरान आग इतनी ज्यादा फैल गई कि 60 से ज्यादा कर्मचारी झुलस गए। फिलहाल मौके पर आग पर तो काबू पा लिया गया है। मगर कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची।



फिलहाल मौके पर आग पर तो काबू पा लिया गया है। मगर कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची।

आतंकवाद पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन यासीन मलिक की पार्टी पर पांच साल के लिए बड़ा प्रतिबंध

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आतंकवाद पर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद यासीन मलिक गुट) पर लगा बैन पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका नया कदम जेकेएलएफ-वाई नामक संगठन के खिलाफ प्राप्त इनपुट अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल



अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल

है, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है। गृह मंत्रालय ने 22 मार्च 2019 को जेकेएलएफ-वाई को एक गैरकानूनी पार्टी घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने बताया कि जेकेएलएफ-वाई अभी भी भारत की संयुक्ता और क्षेत्रीय

लोस चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, 15 रुपए कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम में भारी कटौती कर दी है। भारत के लक्षद्वीप द्वीप में एंड्रोटी और कल्पेनी द्वीप के लिए 15.3 रुपए प्रति लीटर, कावारती और मिनिर्कोय के लिए 5.2 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है। पेट्रोल और डीजल के नए दाम आज से प्रभावी होंगे। बता दें कि अब लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए/लीटर और डीजल के दाम 95.71 रुपए/लीटर होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 2



कटौती की गई है। पेट्रोल और डीजल के नए दाम आज से प्रभावी होंगे। बता दें कि अब लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपए/लीटर और डीजल के दाम 95.71 रुपए/लीटर होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 2

विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव सम्पन्न आइंस्टीन वर्ल्ड रिकार्ड्स ने विश्व कीर्तिमान का दिया प्रमाण पत्र

नई दिल्ली (हि.स.)। साहित्य अकादमी के तत्वावधान में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव-2024 का शनिवार को समापन हो गया। छह दिवसीय इस समारोह का अंतिम दिन दिव्यांग लेखकों के नाम रहा। दिव्यांग लेखकों को राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जगाने को लेकर दिल्ली एवं पनसीआर के 850 से ज्यादा बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया



गया। आज के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में गोपीचंद नारंग के जीवन और कृतित्व पर परिसंवाद, बहुभाषी, रिकार्ड्स, दुबई की टीम ने एक सादे समारोह में इस विश्व कीर्तिमान का

बहुसांस्कृतिक समाज में अनुवाद, भारत की भाषाओं का संरक्षण, भारतीय संदर्भ में पुनर्लेखन/पुनःसृजन के रूप में अनुवाद, भारतीय अंग्रेजी लेखन और अनुवाद के अतिरिक्त भारतीय वाचिक महाकाव्य एवं स्वातंत्र्योत्तर भारतीय साहित्य पर चल रही राष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी समापन हुआ। छह दिवसीय इस समारोह को दुनिया का सबसे बड़ा साहित्योत्सव मानते हुए आज आइंस्टीन वर्ल्ड

सौ प्रतिशत आश्वस्त हूँ कि सीएए से एक भी व्यक्ति असम में नहीं आएगा : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सीएए राज्य में लागू होगी वैसे ही बंद किए गए 27 लाख लोगों के बायोमेट्रिक को अनलॉक किया जाएगा। दरअसल, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को अपडेट करने के दौरान यह प्रक्रिया लॉक कर दी गई थी। खबरों के अनुसार, एनआरसी को अपडेट करने के दौरान राज्य में करीब 27 लाख लोगों के



कहेंगे और उम्मीद है कि चुनाव के तुरंत बाद कोई समाधान निकल आएगा। शर्मा ने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान, कानून के अधिनियमन के बाद कि हम सीएए के बारे में उठाए गए संदेशों को दूर

बायोमेट्रिक्स लॉक हो गए थे और उन्हें आधार कार्ड नहीं मिल पा रहे थे। शर्मा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और अन्य हितधारकों के साथ प्रक्रिया पर चर्चा

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Ma Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc. **ARTICLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

असम भाजपा ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया

गुवाहाटी। असम की सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य में 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए तीन चरणों में होने वाले मतदान का स्वागत किया है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि 19 अप्रैल को पहला चरण राज्य के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार रंगाली बिहु के बहुत करीब है। उधर कम से कम 400 सीटें जीतने के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के अखिल भारतीय लक्ष्य का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि इस बार असम *अबकी बार 400* पर सुनिश्चित करने के लिए उतरेगा। शर्मा ने एक्स पर राज्य में चुनाव के शेड्यूल के साथ पोस्ट किया कि राज्य में शांति और प्रगति ने जड़ें जमा ली हैं और *फिर एकबार मोदी सरकार के दौरान विकसित असम* एक गांठी है। उन्होंने आगे कहा कि 2014 के बाद से, माननीय प्रधान मंत्री

नरेंद्र मोदी ने असम के लिए वह किया है जो कभी असंभव माना जाता था। पर्यटन मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित समय सारिणी हमारे लिए अच्छी है क्योंकि इसे रंगाली बिहु त्योहार के बाद निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने यह ध्यान में रखा है कि त्योहार 13 से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाता है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा जब त्योहार का उत्साह कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव के बाद दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय होगा। हालांकि, कांग्रेस नेता देब्रज संकिया ने कहा कि पहले चरण का मतदान त्योहार के बहुत करीब है जो राज्य के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने

कहा कि इसके परिणामस्वरूप कम मतदान होने की संभावना है और शायद सरकार यही चाहती है। मालुम हो कि 19 अप्रैल को पहले चरण में पांच सीटों—काजीरंगा, शोणितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़ में मतदान होगा। 126 अप्रैल को दूसरे चरण में भी पांच निर्वाचन क्षेत्रों— दरंग—उदालगुड़ी, डिफू (एसटी), करीमगंज, सिलचर (एससी) और नागांव में मतदान होगा। तीसरे और अंतिम चरण में 7 मई को कोकराझाड़ (एसटी), धुबड़ी, बरपेटा और गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। निवर्तमान लोकसभा में भाजपा के पास नौ, कांग्रेस के पास तीन और एआईयूडीएफ के पास एक सीट है, जबकि असम से एक निर्दलीय विधायक भी है।

बंगाल में चुनाव के तारीख की घोषणा पर तृणमूल नाखुश

कोलकाता (हि.स.)। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पश्चिम बंगाल में सात चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण से लेकर एक जून को सातवें चरण के बीच 44 दिनों के अंदर राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर वोटिंग कंप्लेट होगी। इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने नाखुशी जाहिर की है। हालांकि भाजपा ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत किया है। वरिष्ठ तृणमूल नेता और जय की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से एक या दो चरणों में चुनाव कराने के लिए कहा था। लेकिन पोल पैनल ने पश्चिम बंगाल के लिए सात चरण में चुनाव की घोषणा की है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें लगता है कि इस तरह की चुनाव



व्यवस्था से भाजपा को चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपनी धन शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलेगी। उनके नेता राज्य में अधिक से अधिक रैलियां कर सकेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने निर्वाचन आयोग

(ईसीआई) के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी बंगाल में सात चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार कोई फर्क नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के इतिहास के कारण यहां एक या दो चरण में और भारी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने कहा कि चुनाव कराना संभव नहीं है। हम फैसले से खुश हैं। ईसीआई ने कहा कि वह बाहुबल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मजूमदार ने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है।

ड्रग्स तस्कर को न्यायालय ने भेजा जेल

दक्षिण सालमारा (हि.स.)। दक्षिण सालमारा—मानकाचर जिलांतर्गत मानकाचर थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी में बीती रात गिरफ्तार ड्रग्स तस्कर को पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान मानकाचर के कालो देवानी गांव अर्मांरुल इस्ताम (22) के रूप में की गयी है। मानकाचर पुलिस थाना की एक टीमें ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव में छापामारि हुए नशीले पदार्थों को बरामद किया। पुलिस ने घर से एक्सकाॅफ नामक नशीली कोडीन फॉस्पेट सिरप की 460 बोतलें बरामद कीं। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर अमीरुल इस्ताम को मानकाचर पुलिस स्टेशन ले आई। मानकाचर थाने की पुलिस द्वारा अमीरुल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आज न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

माल लदान में पूसीरे ने बनाया रेकार्ड

गुवाहाटी (हि.स.)। आवश्यक एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) माल अनलॉडिंग में निरंतर रूप से वृद्धि दर्ज कर रहा है। चालू वर्ष फरवरी माह के दौरान 1238 माल दुलाई रैक अनलॉड किये गए जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2023 से फरवरी, 2024 के दौरान, पूसीरे के क्षेत्राधिकार में 12750 हजार से अधिक माल दुलाई रैक अनलॉड किए गए। पूसीरे के सीपीआरओ सब्यसाची डे ने आज बताया है कि पूसीरे ने उक्त महीने के दौरान एफसीआई चावल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, उर्वरक, सीमेंट, कोयला, ऑटोमोबाइल, कंटेनर जैसे सामग्रियों और अन्य वस्तुओं का परिवहन किया है तथाइसे अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न गुड्स शेडों में अनलॉड किया है। चालू वर्ष फरवरी माह के दौरान, असम में मालगाड़ी के 725 रैक अनलॉड किए गए, जिनमें से 397 आवश्यक वस्तुओं से लदे हुए थे। उक्त महीने के दौरान त्रिपुरा में 93 रैक, नगालैंड में 19 रैक, मणिपुर में 02 रैक, अरुणाचल प्रदेश में 07 रैक और मिजोरम में 09 रैक अनलॉड किए गए। इसके अलावा, पूसीरे के क्षेत्राधिकार में उक्त महीने के दौरान पश्चिम बंगाल में 223 माल रैक और बिहार में 174 माल रैक भी अनलॉड किए गए। पूसीरे के महत्वपूर्ण सेवकों पर दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्यों के तेज निष्पादन से माल परिवहन के आवक और जावक गतिविधि बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक और अन्य वस्तुओं के परिवहन में वृद्धि के साथ-साथ माल अनलॉडिंग में भी वृद्धि हुई है।

अरुणाचल में 19 अप्रैल को लोस एवं विस चुनाव के लिए होगा मतदान

इटागर (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव—2024 दोनों चुनाव एक साथ आगामी 19 अप्रैल को होगा। इसकी घोषणा आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने भी की है। अधिसूचना के अनुसार अंतिम अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च, नामांकन की जांच 28 मार्च, नामांकन वापसी 30 मार्च, मतदान 19 अप्रैल और मतगणना 4 जून को होगी। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 8,82,816 है, जिनमें 4,33,760 पुरुष और 4,49,050 महिलाएं हैं। पूरे राज्य में कुल 2,226 मतदान केंद्र हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय के तहत पूरे राज्य में सभी मतदान अधिकारियों और अन्य चुनाव से संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पहले ही शुरू कर दिया गया है।

लोस चुनाव के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में कराए जाएंगे विस चुनाव : राजीव कुमार

नई दिल्ली (हि.स.)। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा की। आयोग ने इस दौरान चार राज्यों सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्रप्रदेश में विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की भी घोषणा की। एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर में हुए बदलावों के बाद परिसेमन की प्रक्रिया दिसंबर 2023 तक चली। परिसेमन के बाद आयोग की जिम्मेदारी राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने की है। इस संबंध में राज्य के राजनीतिक दलों और नेताओं से विचार-विमर्श किया गया जिनका मानना है कि लोकसभा के साथ ही राज्य में भी मतदान कराए जाएं। हालांकि चुनाव मशीरी का मानना इससे अलग था और उन्होंने कटने पर चुनाव को टाला गया है। लोकसभा के बाद तुरंत जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने



कहा कि राज्य में सुरक्षा के हालात गंभीर हैं। विधानसभा की 90 सीटें हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 12 उम्मीदवार होंगे और उन्हें सुरक्षा देनी होगी। यह केवल एक उदाहरण है कि चुनाव कानूनों के लिए सुरक्षा बलों की बड़े स्तर पर तैनाती करनी होगी। लोकसभा चुनावों के साथ यह करना संभव नहीं है। इसी के चलते जम्मू-कश्मीर में बाद में मतदान कानूनों की योजना है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आए थे।

पाकिस्तान के क्वेटा में डीएसपी की गोली मारकर हत्या

इस्लामाबाद (हि.स.)। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के सिबी और बाजौर में दो हमलों में एक डीएसपी और एक आदिवासी बुजुर्ग की मौत हो गई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सिबी के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) खालिद जमान मेरी शुक्रवार को सिबी शहर के बाजार क्षेत्र से गुजर रहे थे। उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने चानक गोल चक्कर क्षेत्र के पास उनके वाहन पर गोलियां चला दीं। पुलिस के अनुसार छह गोलियां लगने से खालिद जमान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें संयुक्त सैन्य अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डीएसपी के सुरक्षा गार्ड की जवाबी गोलीबारी में एक हमलावर घायल हो गया। हालांकि वह अन्य हमलावरों के साथ भाग निकला। पुलिस ने पीछा कर उसे निशतर रोड के पास दबोच लिया।

पृष्ठ एक का शेष

19 अप्रैल से एक...

पर मतदान होगा। इसमें असम की चार, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की सभी दो, गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की चार, दार्द्रा एक नगर हवेली और दमन दीव की सभी दो तथा जम्मू-कश्मीर की एक-एक सीट पर मतदान होगा। इस चरण में अधिसूचना 12 अप्रैल, नामांकन 19 अप्रैल, जांच 20 अप्रैल, नाम वापसी 22 अप्रैल को होगी। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की सभी 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू-कश्मीर की एक सीट पर मतदान होगा। इस चरण में अधिसूचना 18 अप्रैल, नामांकन 25 अप्रैल, जांच 26 अप्रैल, नाम वापसी 29 अप्रैल को होगी। पांचवें चरण में 20 मई को कुल 49 सीटों पर मतदान होगा। इसमें छत्तीसगढ़ की पांच, झारखंड की तीन, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की पांच, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, जम्मू-कश्मीर की एक और लद्दाख की एक सीट पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को अधिसूचना, नामांकन 3 मई, जांच 4 मई और नाम वापसी 6 मई को होगी। छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। इसमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की सभी सात सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 29 को अधिसूचना, नामांकन 6 मई, जांच 7 मई, नाम वापसी 9 मई को होगी। सातवें चरण में एक जून को बिहार की आठ, हिमाचल प्रदेश की सभी चार, झारखंड की तीन, ओडिशा की छह, पंजाब की सभी 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की एक सीट पर मतदान होगा। सातवें चरण में अधिसूचना 7 मई, नामांकन 14 मई, जांच 15 मई और नाम वापसी 17 मई को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 96.8 करोड़ मतदाता हैं जोकि जबकि 2019 में 90 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। इस बार 1.8 करोड़ पहली बार के नए मतदाता हैं जोकि 18 से 19 वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कि हम 1.5 करोड़ मतदान अधिकारियों और 10.5 लाख मतदान केंद्रों के साथ लोकतंत्र का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। चुनाव में 55 लाख से अधिक ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने और दुर्व्यवहार तथा व्यक्तिगत हमलों से बचने की सलाह दी है। राजीव कुमार ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में बाहुबल के अलोकतांत्रिक प्रभाव को रोकने के लिए कई उपाय किये हैं। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डीएम और एस्पपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएपीएफ को पर्याप्त रूप से तैनात किया जाएगा और प्रत्येक जिले में एकीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चेक पोस्ट और ड्रोन का इस्तेमाल होगा।

देशभर में लागू ...

फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी। राजीव कुमार ने कहा कि 18वें लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसे कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके। कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इन्में से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है, जो पहली बार मतदान करेंगे और मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं। कुमार ने बताया कि देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है और 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि आयोग हिंसामुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीईसी ने कहा कि चुनाव अधिकारी देशभर में 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। दो नए निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संघ के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं मतदाताओं से आभार व्यक्त हूँ कि वे क्याही (मतदान वाली) लगवाएं। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए एक

ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय चुनाव इस तरह से कराने का वादा करता है कि वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़े। कुमार ने कहा कि सभी राज्यों में आकलन के बाद हम एक यादगार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को लेकर आश्वस्त हैं। कुमार ने कहा कि आयोग ने 17 लोकसभा, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 राज्यों के चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसामुक्त रहे और लगभग एक भी सीट पर दोबारा चुनाव नहीं हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सात चरणों में मतदान हुआ था। उस चुनाव में कुल 91.2 करोड़ योग्य मतदाता थे, जिनमें लगभग 43.8 करोड़ महिला मतदाता और लगभग 47.3 करोड़ पुरुष मतदाता थे। कुल लगभग 61.5 करोड़ वोट डाले गए थे और 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था। साल 2019 के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 303, कांग्रेस ने 52, तृणमूल कांग्रेस ने 22, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने पांच, माकपा ने तीन और भाकपा ने दो सीटें जीती थीं।

55 लाख ईवीएम...

सम्पलेन को संबंधित करते हुए कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग देश भर में 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संघ भी थे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और मैं मतदाताओं से मतदान में हिस्सा लेने का अनुरोध करता हूँ। उन्का कहना था कि यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। कुमार ने कहा कि आयोग राष्ट्रीय चुनाव को इस तरह से कराने का वादा करता है जिससे विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़े। कुमार ने कहा कि सभी राज्यों में स्थिति का आकलन करने के बाद हम एक यादगार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, 1.5 करोड़ कर्मियों द्वारा संचालित हैं 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख ईवीएम होंगे। कुमार के अनुसार, आयोग ने 17 लोकसभा चुनाव, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं। सीईसी ने कहा कि 97.8 करोड़ पात्र मतदाता हैं जिनमें से 49.72 करोड़ पुरुष मतदाता और 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1.82 करोड़ पहली बार मतदाता हैं उन्होंने कहा कि पिछले 11 राज्यों के चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसा मुक्त थे और लगभग शून्य पुनर्मतदान हुए थे। उन्होंने कहा कि आगे चलकर इसमें और सुधार किया जाएगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सात चरणों में मतदान हुआ था। कुल 91.2 करोड़ पात्र मतदाता थे जिनमें लगभग 43.8 करोड़ महिला मतदाता और लगभग 47.3 करोड़ पुरुष मतदाता थे। कुल करीब 61.5 करोड़ वोट पड़े थे और मतदान प्रतिशत 67.4 फीसदी रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 303 सीटें, कांग्रेस ने 52 और तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीट जीती थी।

पूर्वोत्तर के सात...

मणिपुर और त्रिपुरा में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल को तथा शेष चार राज्य मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय में 19 अप्रैल को मतदान होगा। असम में किस सीट पर कब होंगे चुनाव- असम में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण का मतदान पांच सीटों पर होगा। जिसमें मुख्य रूप से शोणितपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, काजीरंगा और लखीमपुर चुनाव क्षेत्र शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में असम की पांच सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को डिफू, नागांव, दरंग-उदालगुड़ी, सिलचर और करीमगंज चुनाव क्षेत्र शामिल हैं। असम में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 मई को होगा। तीसरे चरण में चार विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। तीसरे चरण में गुवाहाटी, बरपेटा, धुबड़ी और कोकराझार चुनाव शामिल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

मणिपुर : राहत शिविरों ...

सनद रहे कि पिछले साल मई से मणिपुर में मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने 25,000 से अधिक लोगों को बचाया है, जबकि लगभग 50,000 लोग शिविरों में रह रहे हैं।

लोस चुनाव : 85...

स्थायी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं पर जोर, छात्रों को चुनाव प्रक्रिया का उपहार। आयोग ने कहा कि देश भर में 10.5 लाख मतदान केंद्र मतदाताओं

को निर्बाध मतदान अनुभव प्रदान करते हैं, जो सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से सुसज्जित हैं। दिव्यांगों के लिए रैंस से लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता तक, हमारा उद्देश्य समावेशी भागीदारी है। हर आवाज मायने रखती है। चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 के बाद से महिला मतदाताओं की संख्या 928 से बढ़कर 948 हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में बढ़ता लिंग अनुपात महिलाओं के मतदान के अधिकार का जश्न मनाने का प्रमाण है। प्रयासों ने महिलाओं को इस प्रक्रिया में शामिल किया है, 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। कुल मतदाताओं में 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं, 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता जुड़े। इस वर्ष के चुनाव में 85 लाख से अधिक पहली बार महिला मतदाता भाग लेंगी। 82 लाख मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 2.18 लाख शतायु हैं। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे हैं। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवां चरण 20 मई को होना है। 125 मई को छठा चरण और 1 जून को सातवां चरण।

यही समय है ...

पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश और देशवासी आए.एन.डी.आई. गठबंधन के कुशासन से पीड़ित थे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा था, जो बोटलों और पॉलिसी पैरालिसिस से अछूता रहा हो। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए ने देश को खराब परिस्थिति से बाहर निकाला था और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आज विश्व के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा। उनका एक ही एजेंडा बचा है— हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना। उनकी परिवारवादी मानसिकता और समाज को बांटने के षड्यंत्र अब जगता नकार कर रही है। भ्रष्टाचार के अपने ट्रैक-रेकार्ड के कारण वो लोगों से अलग नहीं मिला पा रहे हैं। जनता ऐसे लोगों को कभी नहीं करेगी। पीएम मोदी कहा कि मैं यह साफ तौर पर देख रहा हूँ कि आने वाले 5 वर्ष हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा, जिसमें हम भारत की अगले एक हजार वर्ष को विकास यात्रा का रोडमैप तैयार करेंगे। ये समय भारत के सर्वांगीण विकास, समावेशी समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा।

स्पेयर पार्ट्स की ...

साथ ही आग में झुलसे लोगों को इलाज के लिए सविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर गंभीर रूप से झुलसे लोगों को रेफर कर दिया गया है। गुरग्राम के अस्पताल में कई कर्मचारियों को भेजा गया है। बाँयलर फटने के बाद अफरातफर का माहौल हो गया। लोगों को एक बार तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। आनन फानन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना शुरू किया गया। अभी बाँयलर फटने का कारण सामने नहीं आया है।

यासीन मलिक की ...

है। यह आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में है और जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर उग्रवाद का समर्थन कर रहा है। जेकेएलएफ—बाई भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से को देश से अलग करने के दावों का समर्थन और उकसा रहा है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के इरादे से गतिविधियों में शामिल होकर इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले आतंकवादी और अलगाववादी समूहों का समर्थन कर रहा है। आतंकवाद के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए एक मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग के चार संगठनों जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वानी), जेकेपीएल (बशिर अहमद तोता), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और जेकेपीएल (अजीज शेख) पर बैन लगा दिया है। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक भड़काने और अलगाववाद को बढ़ावा देने में शामिल थे।

लोस चुनाव से ...

रूप प्रति लीटर की कटौती की थी। बता दें कि आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीख एलान करने वाला है और इससे ठीक पहले लोगों के केंद्र की ओर से यह बड़ा तोहफा मिला। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबैत कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सबैत उदक लक्ष्य है। वहीं लक्ष्यद्वीप में पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं, जिन्होंने लक्ष्यद्वीप वासियों को अपना

तापमान	
अधिकतम	न्यूनतम
34°	14°



नरेंद्र मोदी को सभी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं : बीटीसी प्रमुख

आप, कांग्रेस समेत बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल

कोकराझाड़ (हिंस)। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोड़ो ने कहा है कि इस चुनाव में एनडीए समर्थित यूपीपीएल उम्मीदवारों की जीत निश्चित है, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। प्रमोद बोड़ो आज कोकराझाड़ में एक चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश को विकसित भारत बनाने, दुनिया की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष लक्ष्य खड़ा करने और देश की जनता को खुशहाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित कुछ लोगों को छोड़कर आम जनता नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने



कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत उनकी पार्टी यूपीपीएल को कोकराझाड़ की सीट मिली है। इस सीट पर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, साथ ही राज्य के अन्य सीटों पर अपने सहयोगी दल भाजपा

और असम गण परिषद के उम्मीदवारों के लिए कार्य करेगी। एक प्रश्न के उत्तर में प्रमोद बोड़ो ने कहा कि आज बीटीसी की परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले जहां 17 वर्षों के बीपीएफ के कार्यकाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, हिंसा, आपसी भेदभाव आदि हुआ करता था। वहीं, आज हर तरफ शांति है। लोगों के बीच समन्वय की भावना प्रगाढ़ हुई है। लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है। लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान किया गया है। क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल होने की वजह से विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर तरह से बीटीसी क्षेत्र में बदलाव आ गया है, यही वजह है कि लोग यूपीपीएल को यहां जीता दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को और अधिक मजबूत करेंगे।

गुवाहाटी (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के मजबूत कार्यों से आकर्षित होकर आम आदमी पार्टी के असम प्रदेश उपाध्यक्ष जितुल डेका, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रतन बोड़ो, गोलाघाट जिला कांग्रेस अध्यक्ष दादू टाये, बराक टी वर्कर्स डेवलपमेंट कमेटी और ऑल असम कार्वा स्टूडेंट्स यूनियन की कारुण्य चैप्टर कमेटी नेता और दो सौ से अधिक पार्टी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हुए। असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारीका, जयंत मल्लबरवा, प्रदेश महासचिव पुलक गोहाई और पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष



भवेश कलिता की मौजूदगी में पार्टी के मुख्य कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में आयोजित इस समारोह में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष भवेश कलिता ने कहा कि विकसित समाज के निर्माण के हित में

औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। मुझे उम्मीद है कि जो आज शामिल हुए हैं, वे आने वाले दिनों में पार्टी के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और समाज के हित में निष्ठा से काम करेंगे।

मणिपुर पुलिस ने 310 लोगों को लिया हिरासत में इफाल (हिंस)। मणिपुर पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों के उल्लंघन के सिलसिले में 310 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आज बताया कि आवश्यक वस्तुओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर 178 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर 202 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। वाहनों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को व्यापक पैमाने पर तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि पहाड़ी और घाटी दोनों में मणिपुर के विभिन्न जिलों में 136 नाके और जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।

शंकरदेव शिशु निकेतन एसएस विद्यालय के नवनिर्मित भवन और स्मार्ट रूम का उद्घाटन

गुवाहाटी (हिंस)। शंकरदेव शिशु निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तर गुवाहाटी के नवनिर्मित भवन और स्मार्ट रूम का उद्घाटन आज किया गया। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की मां और असम साहित्य सभा की पूर्व उपाध्यक्ष मुगालिनी देवी ने इसका उद्घाटन किया। भवन का निर्माण जादुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा निधि से प्राप्त 10 लाख रुपये की लागत से किया गया है। विद्यालय के सचिव



मुकुटेश्वर गोस्वामी द्वारा संचालित सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुगालिनी देवी ने छात्रों से मातृभाषा और संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह किया। संस्कृत सभी भाषाओं की जनी है। संस्कृत भाषा को जाने बिना कोई भी अपनी मातृभाषा को सही ढंग से नहीं सीख सकता है। उन्होंने आचार्यों से आह्वान किया कि वे संस्कृत भाषा और मातृभाषा को उचित महत्व दें। इसके बाद उप प्रमुख आचार्य जगदीश शर्मा और जितु तालुकदार ने उत्तर गुवाहाटी

हेरोइन के साथ तस्क़र गिरफ्तार

कछार (हिंस)। कछार जिलांतर्गत लखीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्रग्स तस्क़र की कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाते हुए लखीपुर पुलिस की टीम ने एक इनावा कार (डब्ल्यूबी-02वी-8006) को राका। कार से पांच सावुनदानी में छिपाकर लिए गए 63.68 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया।

कांग्रेस के कारण विपक्षी गठबंधन का सत्यानाश : आप

डिब्रूगढ़ (हिंस)। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के कारण कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश तो हुआ ही अब युनाइटेड अपोजिशन फोरम का भी सत्यानाश हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा गठबंधन के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए राज्य की 14 में से 13 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए गए। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा लगातार गठबंधन के सहयोगी दलों को अंधेरे में रखते रहे। गठबंधन के नाम पर व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ने की बात कहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष ने आखिरकार विश्वासघात किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनवार आज यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे स्वयं 2 वर्ष पहले तक कांग्रेस में थे। लेकिन, भूपेन बोरा की नीतियों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस

अध्यक्ष के कारण ही इस चुनाव के मौके पर पार्टी के दो कार्यकारी अध्यक्षों ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आप नेता ने कहा कि दिल्ली समेत अन्य सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आवश्यकता से अधिक सीटें दीं। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं हैं बावजूद इसके दिल्ली में कांग्रेस को तीन सीटें दी गईं। लेकिन, कांग्रेस ने यहाँ हमारे साथ धोखा किया। समझौते के अनुसार आम आदमी पार्टी को असम में तीन सीटें मिलनी चाहिए थीं। उसमें से भी एक गुवाहाटी सीट पार्टी ने छोड़ दिया। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन को टेंगा दिखा दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में वे और उनकी पार्टी लोगों को बताएगी कि कांग्रेस और इसके नेता किस तरह धोखाधड़ी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आप अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता पर कई आरोप लगाए।

जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत

लखीमपुर (हिंस)। खाने की तलाश में अरुणाचल की पहाड़ियों से नीचे आए एक हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। मृतक की पहचान डिब्रेश्वर फुकन के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि बीती देर रात जंगली हाथी ने सबसे पहले गोरुबंधा 2 नंबर गांव के बिपिन फुकन के घर में घुसकर धान के भंडार गृह को तहस-नहस कर दिया। बाद में, वह पास के डिब्रेश्वर फुकन के घर में घुस गया और मां तथा पत्नी के सामने ही हाथी ने डिब्रेश्वर को पैरों तले कुचल दिया, जिससे चलते उसकी मौत हो गयी। स्थानीय लोगों ने रात में वन विभाग को फोन कर इसकी सूचना देनी चाही लेकिन वन विभाग की ओर से फोन कॉल को रिसीव नहीं किया गया।

6.5 करोड़ रुपए का नशीला कफ सिरप बरामद, दो लोग गिरफ्तार

करीमगंज (हिंस)। दक्षिण असम के करीमगंज जिले में त्रिपुरा की सीमा पर चुराईबाड़ी में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की नशीला कफ सिरप बरामद किया गया है। पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक 14-पहिया लॉरी भी जब्त की है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मध्य प्रदेश के अशोकनगर निवासी लॉरी चालक रवि शर्मा और पत्थरकांटी (असम के करीमगंज जिले के अंतर्गत) निवासी सुरीलो



शुक्लावैद्य के रूप में हुई है। बजारीछड़ा थाना अंतर्गत चुराईबाड़ी पुलिस चौकी के प्रभारी प्रणव

मिल्ली ने बताया कि शनिवार की सुबह चिकन दाना से एक 14 पहिया लॉरी (पीबी-13बीडी-5534) उत्तर प्रदेश के बनारस से त्रिपुरा जा रही थी। चुराईबाड़ी निगरानी चौकी पर पुलिस कर्मियों ने लॉरी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मुर्गी दाना की बोतलों के पीछे से 402 कार्टून में 64,320 शीशी नशीला एस्कार्फ कफ सिरप बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि बरामद कफ सिरप स्कार्फ की काले बाजार में कोमत करीब साढ़े छह करोड़ रुपए होगी।

आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई की कार्यशाला आयोजित



गुवाहाटी (हिंस)। आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई ने लोकसभा चुनाव से पहले इकाई के सदस्यों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

समाचार इकाई के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए द असम ट्रिब्यून के

कार्यकारी संपादक पीजे बरुवा ने कहा कि समाचार सामग्री में तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखना महत्वपूर्ण है जिसके लिए आकाशवाणी के पास एक विरासत है। उन्होंने

यह भी कहा कि आकाशवाणी का देश के हर कोने में एक विशाल नेटवर्क और बड़ी पहुंच है और समय की आवश्यकता के अनुसार आकाशवाणी ने खुद को बदला है। अपने अनुभव को साझा करते हुए बरुवा ने कहा कि तथ्य समाचार की आत्मा है और हमें इसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए और अधिकारियों से आकाशवाणी के समाचारों की गरिमा और तटस्थता बनाए रखने का आग्रह किया। कार्यशाला में भाग लेते हुए आकाशवाणी गुवाहाटी के निदेशक (इंजीनियरिंग) आरसी बोड़ो ने कहा कि रेडियो अब नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय है और संगठन इसकी महिमा को बरकरार रख सकता है। सभा को संबोधित करते हुए संचार सलाहकार और सोशल मीडिया विशेषज्ञ सालिक खान ने कहा कि हमारे दैनिक जीवन पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बड़ा है क्योंकि यह बहुत कम समय में जनता को आकर्षित कर सकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को पारंपरिक से अधिक सोशल मीडिया पसंद है और किसी संगठन को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सामग्री तैयार करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित

भाजपा की सांगठनिक बैठक

गुवाहाटी (हिंस)। राजधानी के विशिष्ट स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भवेश कलिता की उपस्थिति में आज एक सांगठनिक बैठक हुई। बैठक के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और प्रदेश भाजपा निर्वाचन प्रबंधन समिति के संयोजक पबित्र मार्चेंडिया ने कहा कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों, प्रभारियों, कई मंत्रियों और विधायकों ने भाग लिया। बैठक में आगामी चुनावों के लिए विधानसभा में 126 निर्वाचन क्षेत्रों के 126 प्रभारी नियुक्त किए गए। ये प्रभारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बूथ स्तर तक जनसंपर्क स्थापित करेंगे और अन्य संगठनात्मक कार्य



करेंगे। उन्होंने प्रवासी पक्षी कोयल की तरह कहकर विपक्षी राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम चुनाव से पहले से ही जनता के संपर्क में हैं और चुनाव के बाद भी संपर्क

जारी रखेंगे। अन्य राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय में ही लोगों तक पहुंचते देखे जाते हैं। इस बार लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।

ज्योतिकुची में ग्लोबल सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने खोला शोरूम

गुवाहाटी (विभास)। निर्माण और नवीकरण समाधानों के लिए प्रमुख गंतव्य ग्लोबल सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लोखरा रोड के सबकुची स्थित केआर मिल्स कंपाउंड में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े शोरूम के आज शुभारंभ किया। शोरूम के उद्घाटन के मौके पर वेद प्रकाश गुप्ता, नीरज गुप्ता, संजय गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ग्लोबल सेरामिक्स प्रा. लि. के निदेशक व युवा उद्यमी राहुल गुप्ता ने कहा कि पूर्वोत्तर में सबसे बड़े शोरूम के रूप में, हमारी नई सुविधा अग्रणी ब्रांडों से उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को एक अद्वितीय चयन प्रदान करती है, जो ग्राहकों को उनकी सभी निर्माण आवश्यकताओं के लिए एक व्यापक वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगी। उत्कृष्टता और ग्राहक सन्तुष्टि के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, ग्लोबल सेरामिक्स प्रा. लि. बिल्डर्स, टेकदारों, आर्किटेक्ट्स और गृहस्वामियों के



लिए खरीदारी का एक अलग अनुभव प्रदान करेगा। हमारे इस शोरूम में उत्पादों की एक विविध श्रृंखला शामिल है, जिसमें रूफिंग सामग्री, फ्लोरिंग विकल्प, प्लंबिंग फिक्स्चर, विद्युत आपूर्ति और बहुत कुछ शामिल है। हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक परियोजना के लिए ग्राहक को बाजार में उपलब्ध बेहतरीन सामग्री

प्राप्त हो। श्री गुप्ता ने कहा कि हम अपना नया शोरूम पेश करते हुए रोमांचित हैं, जो हमारे ग्राहकों को उनके निर्माण प्रयासों में प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा लक्ष्य बिल्डरों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनना है। घर के मालिक गुणवत्ता, विविधता और असाधारण सेवा चाहते हैं। हमारे यह

ओरांग नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या

दरंग (हिंस)। ओरांग नेशनल पार्क में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विदेशी पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य से आकर्षित हो रहे हैं। ओरांग नेशनल पार्क और ओरांग टाइगर प्रोजेक्ट, जिसमें एशियाई महाद्वीप में घनत्व के मामले में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें 24 बाघ, 125 गैंडे हैं। इसके अलावा हाथी, हिरण, नीलगाय और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां हैं। 1985 में अभयारण्य और 1999 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त इस पार्क में दिन-प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों के पर्यटकों के अलावा विदेश के विभिन्न हिस्सों के ज्यादा पर्यटक पार्क में पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने होजाईवासियों को समर्पित किया रेलवे ओवर ब्रिज

होजाई (निंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने होजाई शहर के पुराना बाजार को नया बाजार से होते हुए पश्चिम कर्वा आंगलों को जोड़ने वाली रेलवे ओवरब्रिज को होजाईवासियों को आज समर्पित किया। इसके बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होजाई के लिए आज गर्व का दिन है की बहुत पुरानी समस्या का समाधान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा की अब ट्रैफिक से हो रही समस्या का कुछ हद तक निदान होगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि रेलवे के अधिकारियों से वे बात करेंगे जिससे ओर भी कई समस्याओं पर चर्चा कर उनका निदान करेंगे, जिससे आम जनमानस को फायदा होगा। गौरतलब है कि लंबे समय से होजाईवासी रेलवे ओवरब्रिज के न होने के कारण देर तक रेलवे क्रॉसिंग फाटक बंद होने की वजह से अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज के



इस कार्यक्रम में प्रेम रंजन कुमार (डीआरएम, लमडिंग), होजाई के विधायक रामकृष्ण घोष, लमडिंग के विधायक शिवू मिश्रा, काजीरंगा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद ताशा, भाजपा जिला अध्यक्ष अनूप देव, असम अल्पसंख्यक उन्नयन बोर्ड के अध्यक्ष हबीब मोहम्मद चौधरी, होजाई जिला आयुक्त लचिंत कुमार दास, जिला पुलिस अधीक्षक सौरभ गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति

उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए नया बाजार जहां से उक्त ओवरब्रिज का उद्घाटन किया वहां हजारों की संख्याओं में लोग उमर पड़े। उल्लेखयोग्य है कि सं 2017 के दिसंबर महीने में तत्कालीन रेल राज्य मंत्री राजेंद्र गोहाई ने 45 करोड़ की लागत से बनने वाले उक्त रेलवे ओवरब्रिज की आधारशिला रखी थी। उस समय होजाई के विधायक शिलादित्य देव थे।

संपादकीय

2024 का 'नागरिक शास्त्र'

नागरिकता

संशोधन बिल को 2016 में संसद में पेश किया गया।दिसंबर, 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। जाहिर है कि कानून बनाने की पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन 4 साल 3 माह की लंबी अवधि के बाद कानून की अधिसूचना तब जारी की गई, जब आम चुनाव की घोषणा कुछ दिन बाद होनी वाली थी। इस संदर्भ में अधिसूचना के समय पर कठोर सवाल किए जाने स्वाभाविक हैं। अधिनियम के नियम, उसकी पात्रता और शर्तें आदि तय करने में इतना लंबा वक्त गुजार दिया गया, यह वाकई आश्चर्यजनक स्थिति है। अब एक तरफ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना जारी की गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से इंकार कर दिया है। उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी यह बयान दिया है कि पहले सभी संशयों और असमंजस को दूर कर लेना चाहिए था।

दिसंबर, 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। जाहिर है कि कानून बनाने की पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन 4 साल 3 माह की लंबी अवधि के बाद कानून की अधिसूचना तब जारी की गई, जब आम चुनाव की घोषणा कुछ दिन बाद होने ही वाली थी। इस संदर्भ में अधिसूचना के समय पर कठोर सवाल किए जाने स्वाभाविक हैं। अधिनियम के नियम, उसकी पात्रता और शर्तें आदि तय करने में इतना लंबा वक्त गुजार दिया गया, यह वाकई आश्चर्यजनक स्थिति है। अब एक तरफ नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की अधिसूचना जारी की गई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से इंकार कर दिया है। उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी यह बयान दिया है कि पहले सभी संशयों और असमंजस को दूर कर लेना चाहिए था।

लिनक एनआरसी से है। सीएए के जरिए मुसलमानों के एक तबके की नागरिकता छीनी जा सकती है। ऐसी दलीलें महज अफवाहें हैं और देश में विभाजनकारी हालात पैदा करने को विरोध किया जा रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा में कुछ संगठन आंदोलित हो चुके हैं। याद रहे कि राजधानी दिल्ली के 'शाहीन बाग' इलाके में इसी मुद्दे पर मुसलमानों ने 100 दिन का आंदोलन चलाया था और बाद में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे भी भड़के थे, लिहाजा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 'फ्लैग मार्च' तक निकाला है। फिलहाल करीब 18 लाख 74000 आवेदन इन तीनों पड़ोसी देशों से आ चुके हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी 16.39 लाख पाकिस्तान से आए हैं या आना चाहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू आदि अल्पसंख्यक 1.18 फीसदी, बांग्लादेश में 8.5 फीसदी और अफगानिस्तान में मात्र 0.04 फीसदी हैं। उनके लिए भारत 'मानवतावादी धार्मिक संरक्षक देश' है। ये तीनों इस्लामी देश हैं, लिहाजा कानून में मुसलमानों की नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है। गौरतलब यह भी है कि नागरिकता का ऐस कानून 1955 से हमारे देश में लागू है, जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उसमें 6 संशोधन भी किए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 बना कर इसे व्यापकता दी है। पात्र शरणार्थी एक निश्चित वेबपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकार प्राप्त समिति इस पर अंतिम फैसला लेगी। इसके प्रमुख निदेशक (जगन्नाथ) होंगे और 7 अन्य सदस्य भी समिति में होंगे। कानून के नियमों में स्पष्ट उल्लंघन है कि सीएए में नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। वैसे भी संविधान में उल्लंघन है कि भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। आज जो सीएए विरोधी राजनीतिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वे हिंदू-मुसलमानों की सियासत ही है, ताकि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बंटोए जा सकें। हिंदू आदि का अधिकतम धुर्वीकरण भाजपा के पक्ष में होना चाहिए। इस कानून का विरोध जायज नहीं लगता।

कुछ

अलग

पिंजरे में द्वावत

सियासत

यूं तो महत्वाकांक्षा का दाना है, लेकिन चुगने वालों की द्वावत कई बार पिंजरे में फंसा देती है। अपने-अपने मुकाम के संघर्ष में हिमाचल कांग्रेस के छह विधायक यूं तो एक प्रभावशाली धड़ा हैं, लेकिन सत्ता के संकट में उनके पक्ष में अनिश्चितता है। राज्यसभा सीट गंवा बैठी कांग्रेस भी फिलहाल दूध से धुली नर नहीं आ रही, लेकिन अदालत की पहली दरखास्त पर बागी विधायकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रास्ता आसान नहीं किया। माननीय अदालत ने बागी विधायकों की फरियाद पर चंद टिप्पणियां तो कीं, लेकिन किसी फैसले की शरण उन्हें नहीं दी। जिरह से जुवां तक और जुवां से मुकाम तक, हिमाचल में सरकार बनाना बागी विधायकों के बीच सियासी समीकरण रंग रहे हैं, तो भाजपा के साथ भी सुर जोडने की कलह विद्यमान है। यानी यह मुद्दा घिसट कर पेचीदा और लोकसभा चुनाव का पर्सदीमा शायर बन गया है। इसी संदर्भ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि बागी अपनी कानूनी लड़ाई के लिए पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो बताने के मार्ग पर मील पत्थर लगाने पड़ेंगे। अपने निर्णय की धाक पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया ने जिस शिद्दत से द्किप की सूली पर बागियों की सदस्यता छीनी है, उससे राजनीति बेरहम हुई या सत्ता ने खुद को सलाामत कर लिया। सत्य के दरवाजे पर पहुंचा मुद्दा भले ही बागियों की मुखबिरी कर रहा है, लेकिन हिमाचल के लिए यह घटनाक्रम अपमान की श्रेणी में आकर पड़े-सिखले लोगों के राज्य पर प्रश्न खड़े कर रहा है। लवाल बागियों पर हैं, तो सरकार पर भी उठे हैं और सामने बर्जिश कर रही भाजपा की मांसपेशियों पर भी हैं। बेशक हिमाचल अब मध्यप्रदेश या महाराष्ट्र नहीं बन सका, लेकिन कुल नौ विधायकों के लिए की गई किलेबंदी का गणित इतना भी सरल नहीं कि माथापच्ची न

की जाए। भाजपा की सफलता का चक्र कांग्रेस से कहीं व्यापक, तीव्र व सुदृढ़ है, लेकिन हिमाचल के प्रकरण में कांग्रेस अभी तक विफल नहीं हुई है। भले ही पार्टी से राज्यसभा की एक सीट छीनी ली गई या नौ विधायकों की पेशाबंदी में कांग्रेस के पांच फंसे हैं, लेकिन भाजपा के लिए इस सीरियल की कहानी टेढ़ी हो चुकी है। मामला अदालत की सर्वोच्चता में किस करवट बैठता है, इसे लेकर राजनीतिक चुंबक भी परेशान हैं। बागी विधायकों पर आया विधानसभा अध्यक्ष का फैसला प्रतिकूल बना रहेगा या सुप्रीम कोर्ट से राहत के इंतजार में आगामी सदियां गुजर जाएंगी। जो भी हो, आगामी सोमवार तक सरकार के पास अपना सिक्का जमाने का एक और अवसर तो है ही और इसी के परिप्रेष्य में एक बागी निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और दूसरे कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के पिता एवं पूर्व नौकरशाह राकेश शर्मा के खिलाफ हुई एकआईआर की जद में आई जमीन खिसक रही है या ऐसे तालडूतोड़ हमलों की बिसाल पर सियासी कल्ल हो रहे होंगे। कहना न होगा कि बागी विधायकों की रियासत को बागी होने से बचाने के लिए एक नई या पीछे रह ले, वे हथियारों की खरीद के लिए कोर्ट को इंजांच बनाया जा रहा है। अब संगठन व सत्ता का एक साम्राज्य है और जिसे मुख्यमंत्री चला रहे हैं। बेशक कांग्रेस का आलाकामाने में समन्वय समिति के गठन में सत्ता को संगठन और संगठन को सत्ता के कर्ता बंध दिखाने का प्रयत्न किया है, लेकिन सारे घटनाक्रम का जादू अनेक मुद्दियों में बंद है। और तो और, अदालत ने भी कानून की मुद्दियों में किसी फैसले की तहरीर को छुपा रखा है। समन्वय समिति की खोज में कौल सिंह ठाकुर व रामलाल ठाकुर का आगमन आशा जगता है। कांग्रेस के सन्नाटों में खो भी रहे ऐसे चेतन्य के आगमन से सत्ता का अनुभव पुख्ता हो सकता है। फिलहाल कांग्रेस के रक्षा कवच मुखातिब हैं और सरकार के करतब भी चमक पैदा कर रहे हैं।

यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा बल्कि वंचितों को कानून अधिकार दे रहा है सीएए का विरोध करने वाले लोग मानवता के विरोधी प्रतीत हो रहे हैं

डॉ. आशीष वशिष्ठ

दिवनों नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए देश में लागू हो गया है। इस कानून की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से पास किया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति की मुहर लगाने के साथ यह कानून अस्तित्व में आ गया था। सीएए को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुआ था। केंद्र सरकार ने देशभर में एनआरसी लागू करने की बात कही थी। एनआरसी के तहत भारत के नागरिकों का वैध दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन होना था। सीएए के साथ एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के रूप में देखा गया था। इस कानून को लागू किए जाने को लेकर एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी ओर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। खुशी उन लोगों को है जो बरसों से भारत की नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे थे। इस कानून के लागू होने के बाद उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। विरोध करने वाली जमात में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संगठन हैं। राजनीतिक दल व संगठन इसे पूर्व की भांति तरह अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं, वहीं इसे राजनीतिक दांव भी बता रहे हैं। सीएए लागू होने के बाद विपक्षी दल इस कानून को लेकर देशवासियों को खासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं। असल में, आजादी के बाद से ही अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की समूची मानसिकता राजनीतिक दलों और उनके संरक्षक बनने का दावा करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के ही समझ के अनुसार चलती रही है। सीएए के खिलाफ उठे देशव्यापी विवाद को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। विपक्ष अपने बयानों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को यह संदेश दे रहा है कि इस कानून से उनकी नागरिकता संकट में पड़ जाएगी। सरकार और जिम्मेदार पदां पर आसीन लोग इस कानून से जुड़ी तमाम आशंकाओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन, विपक्ष मुस्लिम समुदाय को गलत जानकारी देकर उपद्रव और हिंसक प्रदर्शनों के लिए परोक्ष रूप से उत्साहता दिखाई दे रहा है। 2020 में विपक्ष ने परोक्ष रूप से कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों और उपद्रव में सहायता की थी। ये खुला तथ्य है। नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन,

बीते

दिनों नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए देश में लागू हो गया है। इस कानून की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से पास किया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रपति की मुहर लगाने के साथ यह कानून अस्तित्व में आ गया था। सीएए को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुआ था। केंद्र सरकार ने देशभर में एनआरसी लागू करने की बात कही थी। एनआरसी के तहत भारत के नागरिकों का वैध दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन होना था। सीएए के साथ एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के रूप में देखा गया था। इस कानून को लागू किए जाने को लेकर एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी ओर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। खुशी उन लोगों को है जो बरसों से भारत की नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे थे। इस कानून के लागू होने के बाद उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। विरोध करने वाली जमात में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संगठन हैं। राजनीतिक दल व संगठन इसे पूर्व की भांति तरह अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं, वहीं इसे राजनीतिक दांव भी बता रहे हैं। सीएए लागू होने के बाद विपक्षी दल इस कानून को लेकर देशवासियों को खासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर रहे हैं। असल में, आजादी के बाद से ही अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की समूची मानसिकता राजनीतिक दलों और उनके संरक्षक बनने का दावा करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के ही समझ के अनुसार चलती रही है। सीएए के खिलाफ उठे देशव्यापी विवाद को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। विपक्ष अपने बयानों के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को यह संदेश दे रहा है कि इस कानून से उनकी नागरिकता संकट में पड़ जाएगी। सरकार और जिम्मेदार पदां पर आसीन लोग इस कानून से जुड़ी तमाम आशंकाओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन, विपक्ष मुस्लिम समुदाय को गलत जानकारी देकर उपद्रव और हिंसक प्रदर्शनों के लिए परोक्ष रूप से उत्साहता दिखाई दे रहा है। 2020 में विपक्ष ने परोक्ष रूप से कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों और उपद्रव में सहायता की थी। ये खुला तथ्य है। नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन,



पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता बिना वैध पासपोर्ट और भारत के वीजा के बिना मिल सकती है। दरअसल, ये लोग उन देशों में अल्पसंख्यक हैं। जाने किस त्रास या संकट में उन्हें उन देशों को छोड़ कर आना पड़ा। यहां के नागरिक न होते हुए भी दिक्कतों, मुसीबतों को गले लगाकर यहां जीवन बिताना पड़ रहा है। इसलिए इन सबको नागरिकता देकर उन्हें यानी भारत में सम्मान दिए जाने के इरादे से यह कानून लाया गया है। ऐसे में अब प्रश्न उठता है कि यह कानून भलाई के रूप में सामने लाया जा रहा है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष का कहना है कि इस कानून में खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है। इस कानून में इन तीनों देशों से आए मुसलमानों को नागरिकता देने से बाहर रखा गया है। कई आलोचकों का मानना है कि इस कानून से मुसलमानों से भेदभाव हो रहा है और ये भारत में समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है। जहां तक विपक्ष के विरोध का सवाल है उसका कहना है कि इस कानून में मुस्लिमों को वंचित क्यों रखा गया? यह समानता के कानून का उपहास उड़ाने की तरह है। सरकार का कहना है कि जिन देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया जा रहा है, वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि बहुसंख्यक हैं। इसलिए उन्हें इस देश में यानी भारत में नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है। वो उनके देश हैं, वे वहां खुशी से रहें। भारत सरकार वंचितों की मदद करना चाहती है, इसलिए इन तीनों देशों के वे गैर मुस्लिम नागरिक जो वर्षों पहले यहां आ गए थे उन्हें सम्मान

दिया जा रहा है। इसमें गलत क्या है? लेकिन अब विपक्ष के इस विरोध की सच्चाई और इसके पीछे छिपी कुत्सित इरादे देशवासियों को समझ आने लगे हैं। यह कानून किसी की नागरिकता का हनन नहीं कर रहा बल्कि वंचितों को कानून अधिकार दे रहा है। यह अधिनियम किसी को बुलाकर भी नागरिकता नहीं दे रहा बल्कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया वे ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े मंत्री और जिम्मेदार लोग इस बात को कई बार कह चुके हैं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। असल में, मोदी सरकार के दस सालों के कार्यकाल में देश में बड़े परिवर्तन और काम हुए हैं। देश की जनता का भरोसा मोदी की गारंटी पर है। दस साल के कार्यकाल के बाद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मोदी सरकार की लोकप्रियता और देशवासियों के उसके प्रति विश्वास से विपक्ष में बेचैनी का माहौल है। ऐसे में कुंठित और मुद्दा विहीन विपक्ष जात पात की राजनीति और मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा किसी मुद्दे की तलाश में रहता है। चार साल पहले सीएए कानून बनने के बाद पदों के पीछे शरह विपक्ष दलों ने मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर भड़काया था। नतीजतन देश में अशांति और भय का माहौल बना। हिंसक प्रदर्शनों में जान माल का नुकसान हुआ। आज भी विपक्ष चार साल पहले वाला माहौल बनाना चाहता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार-बार कह रही हैं कि वे पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि संसद के पारित कानून को लागू न करने देना अवैधानिक ही माना जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सीएए के मुद्दे पर लगातार विभाजनकारी बयानबाजी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, सपा, राजद, वाम दल तथा मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। देश में शरणार्थियों की संख्या की बात करके एरिपोर्ट के अनुसार 199,931 हैं।

दृष्टि

कोण

हाथी क्यों नहीं रहा अब हमारा साथी, कुछ घटनाओं से कीजिए समझने की कोशिश

बीते

एक महीने के दौरान झारखंड और उसके सटे छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब गुस्सेल हाथियों के झुंड ने गांव या खेत पर हमला कर नुकसान पहुंचाया और कम से कम दस लोगों की जान ले ली। जब जंगल में हाथी का पेट नहीं भर पाता, तो वह बस्ती का रूख करता है। हमें समझना होगा कि वह के पर्यावरणीय तंत्र में हाथी एक अहम कड़ी है और उसकी बेचैनी का असर समूचे परिवेश पर पड़ता है। बीते कुछ वर्षों में हाथी से कुचल कर मरने वाले इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी प्रमुख वजह है, हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव। वर्ष 2018 -19 में 457, वर्ष 19-20 में 586, वर्ष 20-21 में 464, वर्ष 21-22 में 545 और वर्ष 22-23 में 605 लोग मारे गए। केरल के वायनाड जिले का 36 फीसदी इलाका जंगल है, जहां पिछले साल हाथियों और इंसानों के टकराव की 4,193 घटनाएं हुईं और इनमें 27 लोग मारे गए। देश में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इंसानों का टकराव बढ़ा है, जिनमें बड़ी संख्या में हाथी भी मारे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 300 हाथी

मारे गए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया की रिपोर्ट 'द क्रिटिकल नीड ऑफ एलीफेंट' बताती है कि दुनिया में इस समय कोई 50 हजार हाथी बचे हैं, जिनमें से 60 फीसदी का आधा भारत है। देश के 14 राज्यों में 32 स्थान हाथियों के लिए संरक्षित हैं। दुनिया भर में हाथियों को संरक्षित करने के लिए गठित आठ देशों के समूह में भारत भी शामिल है। हमारे देश में इसे 'राष्ट्रीय धरोहर पशु' घोषित किया गया है। इसके बावजूद देश में बीते दो दशकों में हाथियों की संख्या घटती हो गई है। वर्ष 2018 में पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने केरल में हाथियों के हिंसक होने पर एक अध्ययन किया था, जिससे पता चला कि जंगल में पारंपरिक पेड़ों को काटकर उनकी जगह नीलगिरी और बाबुल बोने से हाथियों का भोजन समाप्त हुआ और यही उनके गुस्से का कारण बना। पेड़ों की ये किस्में जमीन का पानी भी सोखती हैं, सो हाथी के लिए पानी की भी कमी हुई। वन पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को सहेज कर रखने में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पयावरण-मित्र पर्यटन और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्वानुमान के लिहाज से भी हाथी बेजोड़ हैं। अधिकांश संरक्षित क्षेत्रों में हाथियों के आवास के पास



बस्तियां हैं, जहां के लोग वन संसाधनों पर निर्भर हैं। इसी वजह से हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी है। जंगल में जहां इस विशालकाय जंतु का निवास होता है, वहां आम तौर पर शिकारी और जंगल की कटाई करने वाले घुसने का साहस नहीं करते। इसलिए वहां हरियाली सुरक्षित रहती है और बाघ, तेंदुए, भालू जैसे जानवर भी निरापद रहते हैं। कई सदियों से हाथी अपनी जरूरत के अनुरूप अपना स्थान बदला करते थे। गजराज के आवागमन के इन रास्तों को 'गज-गलियारा' कहा गया। जब कभी पानी या भोजन का

संकट होता है, गजराज ऐसे रास्तों से दूसरे जंगलों की ओर जाते हैं, जिनमें मानव बस्ती न हो। देश में हाथी के सुरक्षित कोरिडोर की संख्या 88 है। इसमें 22 पूर्वोत्तर राज्यों, 20 मध्य भारत और 20 दक्षिणी भारत में हैं। दरअसल, गजराज की सबसे बड़ी खूबी है उनकी याददाश्त। आवागमन के लिए वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी परंपरागत रास्तों का ही इस्तेमाल करते आए हैं। बढ़ती आबादी के भोजन और आवास की कमी को पूरा करने के लिए एनआरसी को काटा जा रहा है। हाथियों को जब भूख लगती है और जंगल में कुछ मिलता नहीं या फिर जल-स्रोत सूखे मिलते हैं, तो वे खेत या बस्ती की ओर आ जाते हैं। काम आबादी के विस्तार, हाथियों के प्राकृतिक वास में कमी, जंगलों में खड़े खड़े होने की आदत यहां है और वहां भी। संन्यास के वक्त आ जा जाए, तो भी देश की चिंता उस इतना सताती है कि उसका संन्यास मुल्ही होता जाता है। यहां त्याग और तपस्या एक मुछोटा बन गई है, और जीवन जीने का उपदेश देना एक रिवाज। जो जिंदगी जी नहीं पाए, वे अपनी अशफलता को रण छोडना नहीं, अपनी तलाश का प्रतीक मानते हैं। कला-संस्कृति का बंद करने वाली उवाच प्रशस्त के रराजुओं में तोल कर हर धान एक ही कीमत बिकता है। वह कीमत है, थोथा चना बाजे घना। बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचवा कर फेसबुक से लेकर सांस्कृतिक समारोहों में घुसपैठ कर जाना एक ऐसा प्रिय शगुन है कि जिसे हर स्थापना का भी तलाशना है। यह स्थापना कहीं भी हो सकती है, केवल लेखन ही नहीं, खेल के मैदान में, खोज तलाश के अन्वेषण में और ऊंचे स्वर में चिल्ला कर उनकी ऐसी उपलब्धियों के चीखो-पुकार में जो कभी आपके पास फटकी नहीं। लेकिन उनकी प्रगति की घोषणा करने में आपने कभी कमी नहीं की। वैसे जब आर्थिक प्रगति के दावे हों तो लगता है ऊंची अटारियों वालों के घर और भी ऊंचे हो गए और गूढ़ बस्तियों के क्रंदन को कोई सुनता नहीं। संघर्ष, प्रगति और निरंतर चलते रहना कितने अच्छे शब्द लगते हैं, लेकिन उनका खोखलापन अजनबी नहीं लगता। क्योंकि यहां संघर्ष का अर्थ है रंगना, प्रगति का अर्थ खोखले आंकड़ों का मायाजाल और निरंतर चलते रहने का अर्थ है एक ही चूत में निरंतर गोलाकार घूमते रहना। यहां रोज परिभाषाएं बदल जाती हैं। यहां समाजवाद को उल्टे रास्ते से पकड़ना का प्रयास शुरू हो गया। पहले कहते थे निर्धन और वंचित को रोजी, रोजगार और थियॉफो के अनावश्यक शोषण पर रोक ही नए समाज का निर्माण करेगी। लेकिन बंधु, समाज का निर्माण तो हुआ नहीं, बल्कि अरबपतियों के धन बढ़ाने का रिकार्ड बनने लगा, नई ऊंचाइयां मिलने लगीं। लीजिये जब पुराने रास्ते दरकिनारा हो गए और सार्वजनिक क्षेत्र को नौकरशाही का पुष्टिदा करके नकारा जाने लगा, अब उसके स्थान पर निजी क्षेत्र को तरक्की का जामिन बना दिया गया, प्रांगित दर के बढ़ने का ऊंचा मीनार बता दिया गया। आज लाखों हाथ नौकरी मांगते हैं, टूटे हुए हाथों को अपना हाथ जगन्नाथ का उपदेश मिल गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजना का आसरा लेकर आर्थिक विकास की दर वहां पहुंचा देनी थी, जहां अर्थव्यवस्था स्वतः स्फूर्त कहला देती थी। लेकिन यह कैसा स्वतः स्फूर्त कि देश का उत्पाद चौबीस प्रतिशत घट गया और आर्थिक विकास दर शून्य से भी उपात प्रतिशत नीचे गिर कर शर्मिन्दा हो गई। इन योजनाओं को बनाने वाला योजना आयोग सफेद हाथी कारार दे दिया गया। अब उसकी जगह प्राट हुआ आनीत आयोग, जिसकी नीति की तलाश हो रही है और आयोग के सदस्य किंकर्तव्यमूढ़ हैं।

देश

दुनिया से

व्यवस्थाएं मानवीय सरोकारों का ध्यान रखें, तभी हासिल होगा सतत विकास का लक्ष्य

पृथ्वी

पर मनुष्य की सामाजिकी उसे हैरत में डालती है। उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि उसने सभ्यता के कितने आयामों में अपना विकास कर रखा है। मनुष्य की इस सृजन संस्कृति से उसके सुख का आकलन किया जा रहा है। सुख का जब सामाजिकीकरण होता है, तो वह अवस्था समष्टिगत प्रसन्नता का कारण बनती है। लेकिन यह सुख ही अब हमारे लिए भारी पड़ने लगा है। भौतिक सुख के लिए प्राकृतिक संसाधनों को दोहन बढ़ता जा रहा है। नतीजतन विभिन्न तरह के संघर्ष एवं तनाव ने हमारे सामाजिक ताने-बाने को व्यापक हानि पहुंचाई है। पृथ्वी के हर कोने में सामाजिक न्याय की मांग हो रही है। विभिन्न देश इन तनावों को भरपूर झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास बहानों की कोई कमी नहीं है। वे अपने अहंकार में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि जन से जुड़ने और उनकी सुनने को राजी ही नहीं होते। ऐसे में संघर्ष और तनाव के मुद्दे घटने के बजाय बढ़े ही हैं। उसी का परिणाम है कि आज विश्व की एक बड़ी आबादी, संघर्ष, आंदोलन एवं अपनी अस्मिता को रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है।

को कल्याणकारी मुल्यक बताता है। वह कभी नहीं मानता कि उनके यहां रिचियों की स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें शिक्षा व रोजगार की स्वतंत्रता नहीं है। ईरान में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। युद्धरत देश भी कभी यह नहीं स्वीकार करेंगे कि उनके युद्ध लड़ने से आम लोगों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। ये देश सामाजिक न्याय क्या करेंगे? जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन बनाने की बात की थी। उस गठबंधन से यह उम्मीद की थी कि इससे दुनिया के लोग टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाएंगे, चुनौतियों से निपटेंगे। उनका यह मानना था कि यह पहले सामाजिक अनुबंध को फिर से तैयार करने पर लक्षित है, जिसे व्यक्ति-आधारित नीतियों से हासिल किया जाएगा और इन प्रयासों में सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया जाएगा। लेकिन उसे कितना अमल में लाया गया? उनके सामाजिक अनुबंध का आधार भी राज्य थे और उनका लक्ष्य महिलाओं एवं युवाओं को लाभान्वित करना था, ताकि सामाजिक स्थितियां बदल जाएं। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि सर्वजन के लिए समाज अवसर उपलब्ध होगा। अति-आवश्यक सेवाओं की सुलभता होगी। जीवन-पर्यंत शिक्षा व प्रशिक्षण, उपयुक्त व शिष्ट रोजगार और सामाजिक संरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। आज मानवाधिकार कार्यकर्ता भी मानने लगे हैं कि सामाजिक न्याय का राज्यों को सुनिश्चित करना है, लेकिन वे उस दिशा में सक्रिय नहीं हैं। वे आज तक एक ऐसा रोड-मैप नहीं तैयार कर पाए, जिससे हमारी अवसररचना ही लक्ष्य का निर्धारक बनती। यदि समय रहते दुनिया के सभी देश इसे समझ सकें, तभी तनाव व संघर्ष कम हो सकेगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे जो सतत विकास लक्ष्य के दावे हैं, वे शायद ही कभी पूरे हो सकेंगे। सभ्यतागत चुनौतियों के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी हमारे समक्ष खड़ी है। इसलिए सामाजिक न्याय के प्रति योजनाबद्ध प्रतिबद्धता आज की मांग बन गई है। समय रहते यदि वैश्विक सहमति के साथ कोई योजना बनती है, तभी सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पहल तो हो रही है।



दर्द भरे जिगर की आवाज...

इस

देश के लोगों को उन कतारों में खड़े होने की आदत हो गई है, जो अंगे नहीं सरकती। वैसे कतारों में खड़े होने की आदत यहां है और नहीं। कतार तोड़ कर आगे बढ़ जाने की धक्कामपेल है। धक्का-मुक्की यहां शूरवीरता मानी जाती है और चोर दरवाजे खोल कर गाड़ी पर आसीन हो जाना एप्यु का धर्म। फिर जो आसीन हो गया, वह नीचे उतरता कहां है। संन्यास के वक्त आ जा जाए, तो भी देश की चिंता उस इतना सताती है कि उसका संन्यास मुल्ही होता जाता है। यहां त्याग और तपस्या एक मुछोटा बन गई है, और जीवन जीने का उपदेश देना एक रिवाज। जो जिंदगी जी नहीं पाए, वे अपनी अशफलता को रण छोडना नहीं, अपनी तलाश का प्रतीक मानते हैं। कला-संस्कृति का बंद करने वाली उवाच प्रशस्त के रराजुओं में तोल कर हर धान एक ही कीमत बिकता है। वह कीमत है, थोथा चना बाजे घना। बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचवा कर फेसबुक से लेकर सांस्कृतिक समारोहों में घुसपैठ कर जाना एक ऐसा प्रिय शगुन है कि जिसे हर स्थापना का भी तलाशना है। यह स्थापना कहीं भी हो सकती है, केवल लेखन ही नहीं, खेल के मैदान में, खोज तलाश के अन्वेषण में और ऊंचे स्वर में चिल्ला कर उनकी ऐसी उपलब्धियों के चीखो-पुकार में जो कभी आपके पास फटकी नहीं। लेकिन उनकी प्रगति की घोषणा करने में आपने कभी कमी नहीं की। वैसे जब आर्थिक प्रगति के दावे हों तो लगता है ऊंची अटारियों वालों के घर और भी ऊंचे हो गए और गूढ़ बस्तियों के क्रंदन को कोई सुनता नहीं। संघर्ष, प्रगति और निरंतर चलते रहना कितने अच्छे शब्द लगते हैं, लेकिन उनका खोखलापन अजनबी नहीं लगता। क्योंकि यहां संघर्ष का अर्थ है रंगना, प्रगति का अर्थ खोखले आंकड़ों का मायाजाल और निरंतर चलते रहने का अर्थ है एक ही चूत में निरंतर गोलाकार घूमते रहना। यहां रोज परिभाषाएं बदल जाती हैं। यहां समाजवाद को उल्टे रास्ते से पकड़ना का प्रयास शुरू हो गया। पहले कहते थे निर्धन और वंचित को रोजी, रोजगार और थियॉफो के अनावश्यक शोषण पर रोक ही नए समाज का निर्माण करेगी। लेकिन बंधु, समाज का निर्माण तो हुआ नहीं, बल्कि अरबपतियों के धन बढ़ाने का रिकार्ड बनने लगा, नई ऊंचाइयां मिलने लगीं। लीजिये जब पुराने रास्ते दरकिनारा हो गए और सार्वजनिक क्षेत्र को नौकरशाही का पुष्टिदा करके नकारा जाने लगा, अब उसके स्थान पर निजी क्षेत्र को तरक्की का जामिन बना दिया गया, प्रांगित दर के बढ़ने का ऊंचा मीनार बता दिया गया। आज लाखों हाथ नौकरी मांगते हैं, टूटे हुए हाथों को अपना हाथ जगन्नाथ का उपदेश मिल गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजना का आसरा लेकर आर्थिक विकास की दर वहां पहुंचा देनी थी, जहां अर्थव्यवस्था स्वतः स्फूर्त कहला देती थी। लेकिन यह कैसा स्वतः स्फूर्त कि देश का उत्पाद चौबीस प्रतिशत घट गया और आर्थिक विकास दर शून्य से भी उपात प्रतिशत नीचे गिर कर शर्मिन्दा हो गई। इन योजनाओं को बनाने वाला योजना आयोग सफेद हाथी कारार दे दिया गया। अब उसकी जगह प्राट हुआ आनीत आयोग, जिसकी नीति की तलाश हो रही है और आयोग के सदस्य किंकर्तव्यमूढ़ हैं।

लोकसभा 2024 के चुनाव में वाराणसी सबसे हाई प्रोफाइल सीट, पीएम मोदी के जीत के अंतर पर निगाहें विरोधी दलों के उम्मीदवारों के लिए जमानत बचा पाना ही उपलब्धि होगी

वाराणसी (हिस)। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया। सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सातवें और आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव होगा। वाराणसी में एक जून को मतदान होगा। चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी सरगमी भी दिखने लगी है। भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जीत की हैट्टिक लगनी तय है। बाकी, कांग्रेस सपा गठबंधन दल के उम्मीदवारों के लिए अपनी जमानत बचा पाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। चुनावी जंग में देश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर प्रधानमंत्री के जीत के अंतर ही लोगों की निगाहें



रहेगी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भाजपा प्रत्याशी को कुल 581022 मत मिला था। दूसरे स्थान पर आप के अरविंद केजरीवाल

अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुल 209238 मत मिला था। केजरीवाल को छोड़ बाकि दलों के प्रत्याशियों की जमानत भी नहीं बची थी। कांग्रेस के अजय राय (अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष) को 75614, बसपा के सीए विजय प्रकाश को 60579 तथा सपा के कैलाश चौरसिया को 45291 मत मिला था। इसी तरह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 674, 664 लगभग 63.62 फीसदी मत पाकर जीत का रिकार्ड बनाया था। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव (अब भाजपा में) 195, 159 कुल 18.40 फीसदी मत और कांग्रेस के अजय राय ने 152, 548 लगभग 14.38 फीसदी मत प्राप्त किया था। चुनावी नजरिए से देखें तो वाराणसी संसदीय सीट पर परिणाम को लेकर सभी आश्वस्त है।

वाराणसी में कुल आठ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें रोहिया, वाराणसी उत्तरी, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी केंद्र और सेवापुरी वाराणसी लोकसभा में हैं। वहीं, पिंडवा विधानसभा क्षेत्र मछलीशहर और शिवपुर और अजगरा विधानसभा क्षेत्र चंदौली संसदीय क्षेत्र में आता है। देश में वर्ष 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे तो उस वक्त वाराणसी जिले में लोकसभा की 3 सीटें थीं। इनमें बनारस मध्य, बनारस पूर्व और बनारस-मोरजापुर थी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में काशी के 19 लाख 39 हजार 255 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में पुरुष मतदाता कुल 10 लाख 53 हजार 293 और महिला मतदाता आठ लाख 85 हजार 827 हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर वोटर्स 135 हैं।

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्टिव मोड पर हुआ प्रशासन

हमीरपुर (हिस)। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इसके साथ ही अब प्रशासन भी एक्टिव मोड पर आ गया और क्षेत्रों के चौराहों पर लगी होर्डिंग और पोस्टरों को हटवाने का काम शुरू कर दिया। जनपद के सुमैरपुर कस्बे में लोकसभा चुनाव की रणधैरी बजते ही प्रशासन का चाबुक कस्बे में लगी होर्डिंग्स बैनर पर चल गया। नगर पंचायत की टीम ने अधिशापी अधिकारी के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों में लगी होर्डिंग्स के अलावा वॉल पेंटिंग को मिटाया। होर्डिंग्स हटाने के दौरान ईओ कुल कमल सिंह, तहसीलदार सदर, राजस्व निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर वकील अहमद मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम चुनावों के लिए शनिवार को चुनाव आयोग की



पत्रकार वार्ता के साथ ही देश में चुनावी बिगुल बज गया जिसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। इसका अनुपालन करना आम आदमी की नैतिक जिम्मेदारी

है। काफी समय से मोहदा कस्बे सहित क्षेत्र होर्डिंग और पोस्टर से घटा हुआ था, जिसे नगरपालिका की टीम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चला कर उतारना शुरू कर दिया।

बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

पटना (हिस)। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद शनिवार को बिहार सरकार के सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं उसके मंत्री होंगे। जारी अधिसूचना के मुताबिक, डिप्टी सीएम सप्राट चौधरी को वित्त और वाणिज्य कर विभाग, दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग जबकि विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। जदयू के मंत्री बने बिजेन्द्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग, प्रेम कुमार को सहकारिता, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास,

संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, सुमित कुमार सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मंगल पांडेय को स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के मंत्री बने नीरज कुमार बबलू को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नीतीश के करीबी कहे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग, लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता भी संरक्षण विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, नीतीश मिश्रा को उद्योग एवं पर्यटन विभाग, नितिन नवीन को नगर विकास आवास विभाग के साथ साथ विधि विभाग, दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व भूमि सुधार और महेश्वर हजारी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का दायित्व दिया गया है।

राजस्थान में पिछले पांच साल चली रूमाल झपट्टा सरकार : भूपेंद्र यादव

अलवर (हिस)। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि पिछले पांच साल राजस्थान में एक रूमाल झपट्टा सरकार चली। जिसमें एक तरफ तो सचिन पायलट तो दूसरी तरफ अशोक गढोलत रहे। जिसमें हमेशा खींचतानी चलती रही। खींचतानी से छात्र, युवा और नौजवान के भविष्य साथ खिलवाड़ हुआ। राजस्थान में हुई परीक्षाएँ लीक हुईं, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में परीक्षा लीक के आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही थी। राजस्थान में भजनलाल सरकार आते ही एसओजी ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। भाजपा सरकार पेपर



लीक मामले में आरोपियों को कड़ी सजा देनी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका अलवर से छात्र राजनीति

उन्होंने कहा कि अलवर के लिए सेंटर गवर्नमेंट से विकास कार्य करवाना उनको प्राथमिकता रहेगी। अलवर में पानी की कमी को देखते हुए इंआसीपी पानी की योजना पर कार्य करेंगे और अलवर के सभी क्षेत्र में पानी आएगा। उन्होंने कहा कि सरिस्का क्षेत्र में एलिबेटेड रोड बनाया जाएगा, जिससे सरिस्का का विकास होगा। अलवर जिला एनसीआर में होने के बावजूद भी अन्य एनसीआर जिलों के परिपेक्ष में अधूरा था लेकिन अब उसके डेवलपमेंट को लेकर वह कार्य करेंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, संजय नरुका, पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

से ही जुड़ाव रहा है। 40 साल से उनका गहरा संबंध अलवर से है। चुनाव जीतने के बाद वह 24 घंटे अलवर की सेवा में तत्पर रहेंगे।

पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती : योगी आदित्यनाथ

मुरादाबाद (हिस)। जनपद के डॉ. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज व पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में शनिवार को 2774 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को पारिसिंग आउट परेड संपन्न हुई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षु दरोगाओं को पारिसिंग आउट परेड की सलामी ली और नए दरोगाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस सेवा में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती हैं। आपकी कर्तव्य परापूर्णा पीठेंडि की समस्या का समाधान कर सकती हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। इसके पूर्व मुरादाबाद के इन तीनों संस्थानों समेत 11 स्थानों पर हुई पारिसिंग आउट परेड हुई। जिसमें कुल 8362 प्रशिक्षु दरोगा पास आउट हुए। इनमें



1618 महिला दरोगा शामिल हैं। सीएम के इस संबोधन का उत्तर प्रदेश के 11 पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों पर लाइव प्रसारण हुआ। पारिसिंग आउट परेड में मुरादाबाद के डॉ. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी में 749 प्रशिक्षु दरोगा, पुलिस ट्रेनिंग कालेज में 1136 प्रशिक्षु दरोगा और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 889 प्रशिक्षु महिला दरोगा शामिल रहे।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पीटीसी सीतापुर, एटीसी सीतापुर, पीटीएस गोरखपुर, पीटीएस जालौन, एपीटीसी चुरी, पीटीएस सुल्तानपुर, पीटीएस उन्नाव में पारिसिंग आउट परेड संपन्न हुई। डॉ. बीआर आंबेडकर पुलिस अकादमी के एडीजी राजीव सभरवाल ने स्वागत संबोधन दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों एवं आपके परिवारजनों को भी बधाई देता हूँ। प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षु उन्नाव पसीना बहाता है, उसे चुनौती के मैदान में अधिक खून नहीं बहना पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षुओं को फौरेसिक साइंस, साइबर क्राइम के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दी गई

होगी। जिस विश्वास के साथ आपको जनसेवा में भेजा जा रहा है, उस पर आपको खरा उतरना है। अपने कर्तव्य पालन के साथ अनुशासन का भी ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बड़ी ही शांति के साथ संपन्न हुए। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम बहुत ही शांति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर उग्र के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, विधान परिषद सदस्य व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली चौहान, नगर विधायक रिंतेश गुप्ता, लोकसभा संयोजक डा विशेष गुप्ता उपस्थित रहे।

लोकसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे : चंपाई सोरेन

रांची (हिस)। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। सभी सीटों पर गठबंधन जीतना। हेमंत सोरेन के दुमका से चुनाव लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर कैडर, हर नेता को तैयार किया है और वह चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक-दो दिन में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने राजनाथ सिंह के झारखंड दौरे पर कहा कि जिसके मन में बय होता है वह निकलकर सामने आ जाता है और यही राजनाथ सिंह के साथ भी हुआ है। राहुल की रेली में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हम कल बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हमारा परिवार नाम से एक गीत लांच करने पर चंपाई सोरेन ने कहा कि देश में अलग-अलग समुदाय, अलग-अलग भाषा और संस्कृति हैं।

लोकसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेंगे : चंपाई सोरेन

चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता चुनाव में कालेधन का नाला खोलने वाली : सुशील मोदी

पटना (हिस)। पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 18वें लोकसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत करते हुए शनिवार को यहां कहा कि इससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तेजी दिखाकर चुनावी बांड के आंकड़े सार्वजनिक करायें, वह न्यायिक सक्रियता चुनावों में कालेधन का प्रवाह रोकने की मंशा के अनकूल नहीं है। यह फैसला सीवेरज ट्रेटमेंट प्लांट को तकनीकी कार्रवाई से बंद कर गिरे नाले (काला धन) को सीधे नदी में खोलने-जैसा है। सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि चुनावी बांड और नकद चंदे के अलावा राजनीतिक दलों को किस प्रकार चंदा लेना चाहिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय बताये कि यदि लोग अपनी पसंद के दल का आर्थिक सहयोग कर चुनावी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहें, तो सही तरीका क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ के जो चुनावी बांड भुनाए गए उससे सर्वाधिक 303 सांसदों वाली पार्टी भाजपा को 6 हजार करोड़ रूपए मिले। शेष 14 हजार करोड़ रूपए तो 242

सांसदों वाले विपक्ष को मिले। मोदी ने कहा कि यदि चुनावी बांड गलत हैं, तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद ने सबसे ज्यादा 72 करोड़ 50 लाख के बांड क्यों भुना लिए? राजद चुनावी बांड भुनाने वाले टॉप टेन दलों में है। कांग्रेस ने 1400 करोड़, टीएमपी ने 1600 करोड़ और द्रमुक ने 639 करोड़ के चुनावी बांड भुनाए। बिहार के वित्त मंत्री रह चुके सुशील मोदी ने कहा कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने यह सुनिश्चित किया था कि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान कालेधन से चुनावी बांड न खरीद सके। इसके बावजूद इस बांड पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जिस दल की जितनी लोकप्रियता है या जिसके जितने सांसद-विधायक हैं, उसे यदि उसी अनुपात में अधिक चंदा मिला, तो इसमें घोटाला या स्कैम क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसा आभास होता है कि उसने कोई घोटाला उजागर कर दिया है। मोदी ने कहा कि यदि चुनावी बांड के और आंकड़े सार्वजनिक हुए तो कांग्रेस और राजद मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।

पीसीडीए पेंशन प्रयागराज का सहरसा में करेगा आउटरीच कैंप का आयोजन

सहरसा (हिस)। प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस एकाउंट्स पेंशन प्रयागराज का दो दिवसीय आउटरीच कैंप कोसी कमिश्नरी मुख्यालय सहरसा में तय हुआ है। आजादी के बाद यह पहला ऐसा कैंप कोसी सीमांचल या पूरे उत्तर बिहार में कहीं होगा यह कैंप दिनांक 21 मार्च बृहस्पतिवार एवं 22 मार्च शुकुवार को राधा देवी विवाह भवन रक्त काली मंदिर मत्स्यगंधा में होगा है। इस कैंप में प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा प्रयागराज स्वयं अपने दोआईडीएएस अधिकारी 12 सदस्यों टीम के साथ मौजूद रहेंगे। पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि पीसीडीए प्रयागराज उक्त तिथि को कोसी की धरती सहरसा से ही अपने कार्यों का संचालन करेंगे। साथ ही कोसी- सीमांचल सहित पूरे बिहार के सभी पूर्व सैनिकों वीर नारियों का पेंशन, स्पर्स, डिसेबिलिटी पेंशन, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन बढ़ाव सहित हर

समस्या का तत्काल समाधान करेंगे। साथ ही पूर्व सैनिक परिवारों को संबोधित/संवाद कर हर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। श्री ज्ञान ने बताया कि पीसीडीए पेंशन प्रयागराज देश की इतिहासी संस्था है। जो डिफेंस पेंशनर्स के हितों का ख्याल रखती है तथा सेवाविभूति पश्चात वेतन, पारिवारिक रक्षा, भत्ता, डीए, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता, मेडिकल भत्ता, युद्ध विकलांग भत्ता, सहायता आदि का भुगतान तथा लेखा-जोखा रखती है। यह संस्था सेना के तीनों अंगों के रिकार्ड से जुड़े होते हैं। किसी भी तरह की समस्या पेंशनरों को आने पर सहायता भी करती है। ज्ञात हो कि रक्षा लेखा नियंत्रक पहले डिफेंस पेंशनरों को पेंशन बैंक (सीपीपीसी) के माध्यम से देती थी। पेंशनरों को अपने पेंशन के लिए बैंक पर ही निर्भर रहना पड़ता था और वहीं अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता था। मगर केंद्र सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन करते हुए

बैंक की जिम्मेदारी खत्म कर रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा नियंत्रक को अपने हाथ में लेने को मंजूरी दी तथा पिछले तीन वर्षों से यह प्रक्रिया चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत एक अभियान जिसका नाम स्पर्स रखा गया है। इसे पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिया गया है। इस एप में पेंशनरों के सर्विस रिकार्ड होते हैं तथा इसी पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी देना होता है। एप बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान में ममनाना रकैया एवं शिकायतों को भ्रमरार होने पर निर्णय लिया गया है। अब चुकी अधिकांश पेंशनर वीर नारियां डिजिटल कंप्यूटर ज्ञान से वंचित है अतः शुरुआत में काफ़ी परेशानियां आ रही है। स्पर्स एप में आए हुए सुझाव से संशोधन किया जा रहा है जिसका जिम्मा देश की प्रसिद्ध आईटी कंपनी टीसीएस के पास है। यह आउटरीच कैंप पेंशनरों को आए बदलाव एवं ऑनलाइन जानकारी में प्रशिक्षण के अलावा पेंशनरों के किसी भी तरह की समस्या के समाधान का संघटन है।

सहरसा में करेगा आउटरीच कैंप का आयोजन

बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में होगा चुनाव सफाई कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति, काम पर लौटे सफाईकर्मी

पटना (हिस)। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को लोकसभा चुनाव-2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवें चरण का मतदान 01 जून को होगा। चार जून को कार्डटिंग होगी। बिहार में पहले चरण में 19 अप्रैल को नक्सल प्रभावित क्षेत्र औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में चुनाव होगा। तीसरे चरण में 7 मई को कोसी क्षेत्र के झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया में मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को मिथिलांचल के दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और पांचवें चरण में 20 मई को तिरहुत रेंज के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में चुनाव होगा। छठे चरण में 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज, सोवाग जबकि सबसे अंतिम फेज सातवें चरण में 01 जून को मगध रेंज के नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद में मतदान होगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस हुई। जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इस दौरान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू भी मौजूद थे।



जयपुर (हिस)। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को हड़ताल खत्म कर दी। राज्य सरकार से शनिवार को वार्ता में पांच बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद सफाई कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया गया। शनिवार शाम से जयपुर शहर में सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे और सफाई व्यवस्था बहाल हो जाएगी। पांच दिन से चल रही हड़ताल के चलते शहरभर में जगह-जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। समझौता होने के बाद सफाईकर्मचारी शहर को साफ करने में जुट गए हैं। रविवार को छुट्टी होने पर भी शहर में साफ-सफाई काम काम होगा और पटरी से उतरी सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। संयुक्त वाल्मीकि एम सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष पर लगातार 5 दिन से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। शनिवार को राजस्थान के सफाई कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों एवं संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के कर्मचारियों की मीटिंग ग्रेटर नगर निगम लाल कोठी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों मौजूद रहे। इस बैठक में स्वायत्त



शासन मंत्री श्याम सिंह खरी, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश ओला एवं अतिरिक्त निदेशक श्याम प्रताप शेखावत की मौजूदगी में पत्र पर सफाई कर्मचारियों की शासन द्वारा मांगों पर सहमति बनने पर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करने पर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ द्वारा घोषित सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। समझौता होने के बाद अब सफाईकर्म अतिरिक्त समय देकर शहर को

साफ सुथरा बनाएंगे। अवकाश होने पर भी रविवार को सफाई का काम किया जाएगा। संघटनों की मांग के अनुसार वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2012 एवं सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2018 के अन्तर्गत अत्यावेदनों के लिए दिए गए निर्णय के संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिए जाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जिस पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं होगा। उक्त निर्णय सफाई कर्मचारी यूनियनों की मांग के आधार पर उनकी सहमति से किए गए हैं। यदि इस संशोधन की वजह से यदि कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में भविष्य में इसका उत्तरदायित्व स्वायत्त शासन विभाग पर नहीं डाला जावेगा। हड़ताल अवधि के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जावेगी एवं उक्त अवधि का वेतन आदि नहीं काटा जाएगा। इस समझौते के साथ ही शनिवार को को हड़ताल समाप्त कर दी गई।

सफाई कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति, काम पर लौटे सफाईकर्मी

मोहभंग : आदित्य साहू

रांची (हिस)। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रवक्ता डॉ. बिरसा उरांव, बेदिया विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीतनाथ बेदिया, समाजसेवी डॉ. जयप्रकाश, भुईया समाज कल्याण समिति कोल्हान क्षेत्र के उपाध्यक्ष पोरेश नायक, तांती समाज कोल्हान क्षेत्र के अध्यक्ष राशानंद कुमार तांती, समाज सेवी अशोक कुमार सहाय, समाजसेवी छेत्र लोहरा में समर्थकों के साथ पार्टी का सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने सभी नेताओं को माला एवं पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया। साहू ने कहा कि परिवारवादी पार्टी कांग्रेस-झामुमो से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है और बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति-नियत एवं नेतृत्व से प्रभावित होकर दूसरे दलों से लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. बिरसा उरांव ने कहा कि कांग्रेस-झामुमो आदिवासीयों को विप्रभित कर रही है।



स्मॉल-मिडकैप शेयरों का 15 माह में सबसे खराब प्रदर्शन; निवेशकों के 5.81 लाख करोड़ रुपये डूबे

बंगलूरु। पूंजी बाजार नियामक सेबी की ओर से स्मॉल और मिडकैप शेयरों के बारे में जताई गई चिंता से इस हफ्ते में इन दोनों इंडेक्स में निवेशकों के 5.81 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं। इसके अलावा, सेबी ने म्यूचुअल फंड को इन शेयरों में एकमुश्त निवेश को सीमित करने का भी सुझाव दिया है। इससे इनमें जबरदस्त बिकवाली देखी गई। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के बयान के बाद पिछले 15 माह में इन शेयरों का इस हफ्ते सबसे खराब

प्रदर्शन रहा है। म्यूचुअल फंडों ने अब तनाव परीक्षणों के नतीजों का खुलासा करना शुरू कर दिया है। इससे निवेशकों ने इन फंडों से पैसा निकालना शुरू दिया है।
दोगुना बढ़ गया मूल्य
निफ्टी स्मॉलकैप-100 इंडेक्स का मूल्य एक साल में करीब दोगुना बढ़ा है। मिडकैप-60 फीसदी तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हवाला ऑपरेटर्स के पास भी 30 कंपनियों से ज्यादा के शेयर दुबई स्थित कथित

हवाला ऑपरेटर व संबंधित संस्थाओं के पास 30 से अधिक कंपनियों के शेयर हैं। आरोपियों के पोर्टफोलियो वाले शेयरों ने कई गुना रिटर्न दिया है। जेनसोल इंजीनियरिंग ने दो वर्षों में 8 गुना रिटर्न दिया है।
महादेव एप में शामिल कंपनियों का हिस्सा
कई स्मॉलकैप और छोटे शेयरों में महादेव ऑनलाइन एप में शामिल कंपनियों की भी हिस्सेदारी है। इनका करोड़ों का निवेश है।

महादेव ऑनलाइन बुक घोस्टले के कारण स्मॉलकैप निवेशकों को नुकसान हुआ है। घोस्टले से जुड़े कई शेयरों में भारी गिरावट आई है।
विदेशी मुद्रा मंडार दो साल के उच्च स्तर पर
देश का विदेशी मुद्रा मंडार 8 मार्च को समाप्त सप्ताह में 10.47 अरब डॉलर बढ़कर दो साल के उच्च स्तर 636.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

न्यूजबीफ

खुदरा कर्ज के साथ टॉप-अप होम लोन पर जांच बढ़ी, पर्सनल लोन देने वाले संस्थानों को लगाने लगाने को कहा



मुंबई। आरबीआई ने जोखिम को देखते हुए खुदरा कर्जों की जांच और बढ़ा दी है। साथ ही, टॉप-अप होम लोन को भी जांच के दायरे में ले लिया है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, खुदरा कर्ज में आई बेतहाशा तेजी से वित्तीय प्रणाली में जोखिम बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए जांच को और फैला दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों और एनबीएफसी की ओर से इस तरह के कर्ज पर निगरानी बढ़ा दी है। पर्सनल लोन देने वाले संस्थानों को ऐसे कर्ज पर लगाने लगाने को कहा गया है जहां जोखिम ज्यादा बढ़ रहा है। आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय फर्मों की ओर से कुछ खुदरा ऋणों पर लगाने लगाने के लिए छह महीनों में कई कदम उठाए हैं। इसमें उनको चेतावनी भी दी है। सूत्रों के अनुसार, आरबीआई का रुख अब बदल गया है। उसने सितंबर में कहा था कि ज्यादा उधारी से वित्तीय प्रणाली का कोई जोखिम नहीं है। लेकिन अब नई जांच वित्तीय फर्मों के लिए एक बड़ा झटका है। एक सूत्र ने कहा, आरबीआई विशेष चेतावनियों पर अब चार चरणों की जांच कर रहा है। इसमें निगरानी करना, चेतावनी देना, दंडित करना और फिर कार्रवाई करना। आरबीआई विशेष चेतावनियों के आधार पर संस्थाओं को सही दिशा में कदम उठाने का मौका देना चाहता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद कर्ज में तेजी पिछले दो वर्षों में आरबीआई के रेपो दर में 2.5 प्रतिशत बढ़ोतरी के बावजूद बैंकों का कर्ज सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़ रहा है। जबकि वित्त वर्ष में जीडीपी की अनुमानित 7.6 प्रतिशत की वृद्धि से दोगुना से भी अधिक है। जनवरी के अंत में असुरक्षित पर्सनल लोन एक साल पहले की तुलना में 21 प्रतिशत बढ़ गए थे। बैंक गलत तरीके से कर रहे विज्ञापन अब मॉर्गेंज टॉप-अप पर बारीकी से नजर रख रहा है। मॉर्गेंज लोन मूलरूप से घर में मरम्मत या अतिरिक्त सुविधाओं के लिए होते हैं। लेकिन बैंक उन्हें शादीयों, छुट्टियों और व्यापार में निवेश के लिए इसका विज्ञापन कर रहे हैं। (को-लेंडिंग कम करें बैंक आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी को एल्योरिथम आधारित क्रेडिट मॉडल के जोखिमों के बारे में आगाह कर रहा है।) कुछ संस्थानों को सह-उधार (को-लेंडिंग) कम करने के लिए कहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिधर दास ने दिसंबर में पर्सनल लोन पर कहा था, हम घर में आग लगाने और फिर कार्रवाई करने का इंतजार नहीं करते हैं।

अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना होगा और आसान, सेबी ने कई उपायों की दी मंजूरी



मुंबई। नियामक सेबी ने शेयर बाजार में व्यापार को बेहतर और आसान बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दे दी है। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से एक जुटाने की चाहत रखने वाली संस्थाओं को छूट प्रदान करना शामिल है। सेबी बोर्ड ने अपनी बैठक के दौरान प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सेबी ने एक विज्ञापन में कहा कि अन्य बातों के अलावा, नियामक ने इंडिटी शेयरों के सार्वजनिक/राइट्स इश्यू में एक प्रतिशत सुरक्षा जमा की आवश्यकता को खत्म करने और अप्रत्याशित घटना के कारण कॉपी संपादन लिथि को बढ़ाने में लचीलापन प्रदान करने का निर्णय लिया है। फंड जुटाने में भी मिलेगी सुविधा बता दें कि बोर्ड के ये उपाय आईपीओ और फंड जुटाने के लिए आने वाली कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने वाला प्रयास है। इसके अलावा बोर्ड ने एफपीआई द्वारा भौतिक परिवर्तनों के खुलासे के लिए समयसीमा में ढील देने को भी मंजूरी दे दी है। हितधारकों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने 25 शेयरों की सीमित सेट और दलालों के सीमित सेट के साथ वैकल्पिक टी+0 निपटान के बीटा संस्करण के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। विज्ञापन में आगे कहा गया कि इसके समानांतर, सेबी बीटा संस्करण के उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों के साथ आगे परामर्श करना जारी रखेगा। इसके अलावा, नियामक इस कार्यान्वयन की तारीख से तीन महीने और छह महीने के अंत में प्रगति की समीक्षा करेगा, और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। सेबी ने व्यापार करने में आसानी को सुधार लाने के उद्देश्य से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विभिन्न छूटों को भी मंजूरी दी।

मुक्त व्यापार समझौते पर भारत-ब्रिटेन की बातचीत थमी, लोकसभा चुनाव के बाद होगा फैसला

लंदन। भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत थम गई है। दरअसल भारत में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो जाएगा, जिसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर 14 दौर की वार्ता के बाद रुकने का फैसला किया है और अब लोकसभा चुनाव के बाद ही इस दिशा में कोई फैसला हो सकेगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि बातचीत थमने का पहला से ही अनुमान था क्योंकि भारत में आम चुनाव होने हैं और अब चुनाव के बाद ही मुक्त व्यापार समझौते पर आगे कोई औपचारिक बातचीत हो सकती है। भारत और ब्रिटेन के बीच जनवरी 2022 में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी।

मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत ब्रिटेन ने जताई प्रतिबद्धता

एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों में से कोई भी समझौते से पीछे हटने के मुद्दों नहीं हैं, लेकिन अभी तक समझौता न होने की वजह ये है कि हमें अभी तक वो डील नहीं मिली है, जिस पर दोनों पक्षों में सहमति बन सके। दोनों पक्षों के मध्यस्थों ने बीते कुछ वर्षों में समझौते को लेकर कड़ी मेहनत की है और कई मुद्दों पर हमारे बीच सहमति बन भी गई है। हालांकि अभी माल, सेवाएं और निवेश पर सहमति बननी बाकी है। इस हफ्ते की शुरुआत में पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम रूथ सुनक के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने समझौते को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी।

इन मुद्दों पर अटका है समझौता

एक ब्रिटिश अधिकारी ने बताया कि भारत और ब्रिटेन में महत्वकांक्षी व्यापार समझौते को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कई मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। हम इसे लेकर साफ हैं कि जब तक समझौता निष्पक्ष, संतुलित और ब्रिटेन के लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के हित में होना चाहिए। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बीते हफ्ते ऐसा ही कहा था कि जब तक समझौता भारतीय लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा, हम इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। ब्रिटेन चाहता है कि भारत, ब्रिटेन से



होने वाले निर्यात पर टैरिफ घटाए, जो कि अभी 150 प्रतिशत जितना ज्यादा है। वहीं भारत चाहता है कि ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों के मामले में नियम निष्पक्ष रहें और उन्हें नेशनल इश्योरेंस के तहत कवर किया जाए। वहीं ब्रिटेन की मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत सरकार भी ब्रिटेन में आगामी

आम चुनाव का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश चुनाव में अगर लेबर पार्टी को जीत मिलती है तो भारत को लेबर पार्टी से अच्छी डील मिलने की उम्मीद है। बीते दिनों लेबर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने भी भारत का दौरा किया था और उन्होंने दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी की थी।

नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू, एसएचजी को खेती के लिए मिलेगा ड्रोन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला किसानों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इसके तहत एसएचजी को ड्रोन दिया जाएगा। जिसका इस्तेमाल वो खेती में कर सकेगी, जो आय बढ़ाने में सहायक होगा। मौजूदा समय में देशभर में करीब 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी का हिस्सा हैं। इस योजना के तहत देशभर के 14500 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) को ड्रोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें मोदी सरकार 80 फीसदी सब्सिडी देगी। बचे हुए बीच 20 फीसदी पर लोन दिया जाएगा। इस लोन में भी एक और फायदा है। ब्याज में 3 फीसदी की छूट अलग से दी जाएगी। कृषि मंत्रालय के अनुसार एक ड्रोन पैकेज की संभावित कीमत 10 लाख रुपये के करीब होगी और 10 लाख के ड्रोन में एसएचजी को आठ लाख की सब्सिडी मिलेगी। उसे केवल दो लाख चुकाना होगा और दो लाख का रुपये का लोन दिया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को ड्रोन पायलट को डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव के लिए एक और महिला को को-पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह 15 दिन की ट्रेनिंग इसी पैकेज में शामिल होगी। इस योजना के तहत ड्रोन का इस्तेमाल नैनो फर्टिलाइजर और कीटनाशक के छिड़काव में इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना को लागू करने में देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की मदद ली जाएगी।

आम चुनाव का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश चुनाव में अगर लेबर पार्टी को जीत मिलती है तो भारत को लेबर पार्टी से अच्छी डील मिलने की उम्मीद है। बीते दिनों लेबर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने भी भारत का दौरा किया था और उन्होंने दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी की थी।

दावा- अमेरिका अदाणी समूह के खिलाफ घूस देने की आशंका की जांच कर रहा, कंपनी ने कहा- हमें जानकारी नहीं

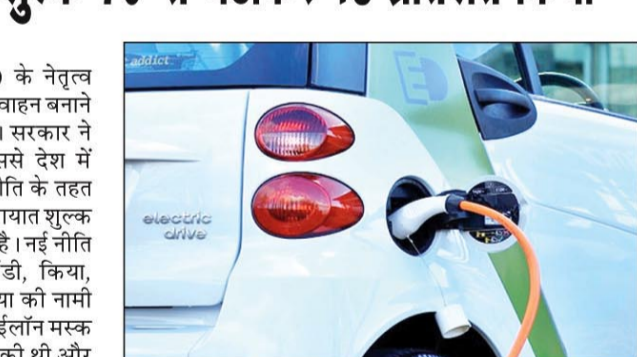
नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत के अदाणी समूह की अपनी जांच का दावा बढ़ाया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कंपनी के संस्थापक गौतम अदाणी और कंपनी रिश्वतखोरी में शामिल है या नहीं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में मामले के बारे प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या गौतम अदाणी सहित अदाणी समूह की किसी इकाई या कंपनी से जुड़े लोगों ने एक ऊर्जा परियोजना के लिए भारत में अधिकारियों को भुगतान किया है



धोखाधड़ी इकाई यह जांच कर रही है। इसके साथ ही भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी एन्यूएर पावर ग्लोबल पर भी नजर रखी जा रही है। अदाणी समूह ने इस मामले में बताया, हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी जांच की जानकारी नहीं है। अदाणी समूह के शेयरों और बांडों में पिछले साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखी गई थी। उस समय अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें समूह पर खातों में गड़बड़ी, स्टॉक्स में हेरफेर और टैक्स हेवन के उपयोग का आरोप लगाया गया था। हालांकि, भारतीय कंपनी ने इन आरोपों से इनकार करती रही है।

सरकार ने तैयार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ईवी वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए आयात शुल्क 70 से घटाकर 15 प्रतिशत किया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने आम चुनाव से ठीक पहले इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली वैश्विक कंपनियों के लिए द्वार खोल दिए हैं। सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की है, जिससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण जोर पकड़ेगा। इस नीति के तहत सरकार ने ऐसे वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए आयात शुल्क मौजूदा 70 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। नई नीति अमल में आने के बाद टेस्ला, बिनफास्ट, बीवाईडी, किया, स्कोडा, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज जैसी दुनिया की नामी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार देंगी। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने सरकार से शुल्क में छूट की मांग की थी और नई नीति उसी का नतीजा दिख रही है। नई नीति के तहत विदेश में पूरी तरह तैयार (सीबीयू) ई-कार भारत में आयात की जा सकती है। ऐसी कारों पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा। फिलहाल 40,000 डॉलर से अधिक दाम वाली सीबीयू ई-कार पर 100 प्रतिशत और इससे कम कीमत वाली ई-कार पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब जो नीति तैयार की है, उसके हिसाब से टेस्ला जैसी कंपनियों से सीबीयू ई-कार पर भी 15 प्रतिशत आयात शुल्क ही



वसूला जाता है। टुकड़ों या पुर्जों की शक्ल में (सीकेडी) आने वाली कारों पर अभी इतना ही शुल्क लगाता है। सीकेडी को देश में लाकर असेंबल किया जाता है। सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठकों में टेस्ला कर घटाने की मांग करती रही है। भारी उद्योग मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार कंपनियां स्वयं उत्पादन करती हैं तो उनके उत्पादों पर कम आयात शुल्क लगेगा। लेकिन इन कंपनियों को देश में कम से कम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।

सियासी दलों ने 2015 से 2020 तक पांच साल में प्रचार-प्रसार में खर्च किए 6500 करोड़, आयोग की ऑडिट में खुलासा

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भले ही राजनीतिक दलों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर रखी है, लेकिन पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए खुले हाथों से खर्च करने में पीछे नहीं रहतीं। यहां तक कि अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए करोड़ों रुपये बहाती हैं। निर्वाचन आयोग को दी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में राजनीतिक दलों ने खुद यह बात मानी है। वर्ष 2015 से 2020 तक हुए विभिन्न चुनावों में राजनीतिक दलों ने 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इनमें 11 दल क्षेत्रीय जबकि सात राष्ट्रीय हैं।



कांग्रेस ने 21.41 फीसदी (1,400 करोड़) रकम खर्च की। इसका मतलब कुल 18 पार्टियों में से इन दोनों ने अकेले 77 फीसदी से ज्यादा पैसा खर्च किया है। सपा ने 3.95 फीसदी, डीएमके ने 3.6 फीसदी, वार्डएसआर कांग्रेस ने 2.17 फीसदी, बसपा ने 2.04 और तृणमूल कांग्रेस ने 1.83 फीसदी रकम खर्च की है। 2019-20 में 18 पार्टियों ने कुल

राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने पर भी जमकर खर्च करती हैं। भाजपा ने पांच वर्षों में कुल खर्च 11.41 प्रतिशत उम्मीदवारों की वित्तीय सहायता देने पर खर्च किया है। एनसीपी ने 7.9 फीसदी, टीएमसी ने 5.1 फीसदी, आम आदमी पार्टी ने 2.3 फीसदी और जनता दल (यू) ने 1.7 फीसदी रकम इस मद में खर्च की है।

वास्तविक खर्च का अनुमान मुश्किल

हर चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय है। बावजूद इसके किसी प्रत्याशी ने कितना खर्च किया, इसका वास्तविक अनुमान लगाना मुश्किल है।
सुनावों में प्रमुख खर्च
■ हेलिकॉप्टर एक इंजन- 65,000 रुपये घंटे।
■ हेलिकॉप्टर दो इंजन-3.75 लाख रुपये घंटे।
■ एसयूवी कार : 10,000 प्रतिदिन, होर्डिंग : 20 हजार रुपये। सोफा : 10 से 15 हजार रुपये।
■ होर्डिंग- एक से डेढ़ लाख रुपये। अखबारों व सोशल मीडिया में विज्ञापन 30-42 लाख।

सबसे महंगा चुनाव इस बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च की उम्मीद

अमेरिका स्थित कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक-टैंक में वरिष्ठ फेलो और दक्षिण एशिया कार्यक्रम के निदेशक वैष्णव अनुसु, भारत में 2019 का आम चुनाव भारतीय इतिहास में सबसे महंगा था और संभवतः किसी भी लोकतांत्रिक देश में अब तक के सबसे महंगे चुनावों में से एक था। यह रकम 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। इस साल इसके एक लाख करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद है।
3,400 करोड़ यानी 54 फीसदी रकम सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च
सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने कुल खर्च में से 40.8 फीसदी यानी 560 करोड़ रुपये प्रचार और विज्ञापन पर खर्च किए हैं। 17.47 फीसदी खर्च (250 करोड़ रुपये) चुनावी यात्राओं पर किया गया। 150 गुना बढ़ा : कांग्रेस का खर्च इसी दौरान 8 करोड़ से 50 गुना बढ़कर 400 करोड़ हो गया। 2016-17 की तुलना में 2017-18 में खर्च में 86 प्रतिशत की कमी आई थी।



स्पार्टा को 6-1 से रौंद लिवरपूल क्वार्टर फाइनल में, गाक्पो के दो गोल से यूरोपा लीग में आसान जीत

लंदन। लिवरपूल ने यूरोपा लीग में शानदार प्रदर्शन का क्रम जारी रखते हुए स्पार्टा को 6-1 से रौंदकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अंतिम-16 के पहले चरण में लिवरपूल ने स्पार्टा पर 5-1 से जीत हासिल की थी। बुधस्वतिवार की रात मिली जीत में लिवरपूल के लिए कोडी गाक्पो (14, 55 मिनट) ने दो गोल किए। स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 10वें मिनट में एक गोल दागा। लिवरपूल के लिए अन्य गोल डार्विन नुनेज (7), बाबी क्लार्क (8) और डोमिनिक (48 मिनट) ने किए। स्पार्टा के लिए

एकमात्र गोल बरमेनसेविच ने 42वें मिनट में किया।

लेवरकुसेन अंतिम-8 में

जनवरी में अफ्रीका कप में मिस्र के लिए खेलते हुए चोटिल हो गए सलाह ने दो मैच पहले ही वापसी की है। उनके इस सत्र में 20 गोल हो गए हैं। वह लगातार सात सत्र में 20 या उससे अधिक गोल करने वाले लिवरपूल के पहले फुटबालर बन गए हैं। पहले हाफ में लिवरपूल 4-1 की बढ़त पर था बुधस्वतिवार में शीघ्र पर चल रहे जर्मनी के बायर लेवरकुसेन ने

कजाखस्तान के क्लब कराबाग पर 3-2 से नाटकीय जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक समय लेवरकुसेन 1-2 से पीछे था। पैट्रिक शिक ने स्टापेज समय में दो गोलकर लेवरकुसेन को जीत दिला दी। कराबाग के लिए जुबेर (57) और जुन्हिनो (67) ने गोलकर 2-0 की बढ़त दिलाई थी। लेवरकुसेन के लिए 72वें मिनट में फ्रिमपांग ने पहला गोल किया। पहला चरण दोनों के बीच 2-2 से बराबरी पर खड़ा था।

एसी मिलान, वेस्टहैम भी क्वार्टर

फाइनल में

यूरोपा लीग के अन्य प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में इटैलियन क्लब एसी मिलान ने स्लाविया प्राग को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड के क्लब वेस्टहैम ने पहले चरण में 0-1 की हार से उबरते हुए प्रीमियर लीग के 5-0 से रौंदकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। फ्रांस के क्लब मार्सेली को विलारियल के हाथों 1-3 से हार के बावजूद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला। उसने पहले चरण में 4-0 से जीत हासिल की थी।

न्यूज़ ब्रीफ

चैम्पियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में टकराएंगे रियल और सिटी, बार्सा का पीएसजी से होगा मुकाबला



न्योन (स्विट्जरलैंड)। पिछले दो बार के विजेता टीमों और इस बार ग्रुप के सभी छह में जीतने वाली टीमों रियल मैड्रिड और मैन्चेस्टर सिटी चैम्पियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में टकराएंगी। दोनों के बीच पहला चरण नौ या 10 अप्रैल को मैड्रिड में खेला जाएगा। किलियन एम्बापे की टीम पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना से टकराएंगी। पहला चरण पेरिस में खेला जाएगा। आर्सेनल का मुकाबला हेरी केन की टीम बार्नम म्युनिख से होगा, जबकि एटलेटिको मैड्रिड और बोर्सिया डॉर्टमुंड के बीच अन्य क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल का मुकाबला अटलांटा से, बायर लेवरकुसेन का वेस्टहैम से, बेनफिका का मार्सेली से और एसी मिलान का मुकाबला रोमा से होगा। चैम्पियंस लीग क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल (इंग्लैंड) बनाम बार्नम म्युनिख (जर्मनी) एटलेटिको मैड्रिड (स्पेन) बनाम बोर्सिया डॉर्टमुंड (जर्मनी) रियल मैड्रिड (स्पेन) बनाम मैन्चेस्टर सिटी (इंग्लैंड) पेरिस सेंट-जर्मेन (फ्रांस) बनाम बार्सिलोना (स्पेन) यूरोपा लीग में एसी मिलान बनाम रोमा लिवरपूल बनाम अटलांटा बायर लेवरकुसेन बनाम वेस्टहैम बेनफिका बनाम मार्सेल वया बोले पेप गार्डियोला रियल मैड्रिड 14 बार का चैम्पियन है और उसने 2022 के सेमीफाइनल में सिटी को हरा दिया था, लेकिन काला एसेलोटी की टीम को पिछले साल अंतिम चार में पेप गार्डियोला की टीम ने यूएफए में 5-1 से शिकस्त दी थी। चैम्पियंस लीग में आने के बाद गार्डियोला ने कहा- हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह एक परंपरा की तरह दिखता है। इस लीग के किंग के खिलाफ खेला, जो कि 14 चैम्पियंस लीग खिताब जीत चुकी है। उम्मीद है कि हम अच्छा खेल दिखाएंगे। मैड्रिड में पहले गेम (लेग) से पहले अभी भी तीन सप्ताह बाकी हैं, हम पूरी तैयारी करेंगे। थॉमस टुकेल का बयान बार्नम म्युनिख के कोच थॉमस टुकेल ने झूठ पर कहा- अब हमारा सामना यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक से है। वे दो साल से लगातार शीर्ष स्तर पर खेल रहे हैं। वह एक खतरनाक टीम है। हालांकि, हम तैयार रहेंगे। हम अपने कालिदा की जानते हैं।

रणजी में सबसे अधिक रन बनाने वाले पांच खिलाड़ियों में रिकी भुई सहित चार युवा शामिल रहे



नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी में इस बार युवा खिलाड़ी छाये रहे हैं। इस बार टूर्नामेंट में रिकी भुई, सचिन बेबी सहित चार युवा खिलाड़ियों ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। अनुभवी खिलाड़ियों की बात करें तो केवल चेतनेश्वर पुजारा ही एकमात्र अनुभवी खिलाड़ी रहे जो अधिक रन बना पाये। वहीं हेरानी की बात ये है कि सबसे अधिक रन बनाने वाले में विजेता टीम मुंबई का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इस सत्र में सबसे अधिक रन भुई के नाम रहे। भुई ने इस सत्र में 900 से भी अधिक रन बनाए हैं। भुई ने आंध्र प्रदेश की ओर से खेलते हुए 13 पारियों में कुल 902 रन बनाए हैं। उनका 75 के औसत से सबसे अधिक स्कोर 175 रन रहा है। इस दौरान इस बल्लेबाज ने 4 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं इस सत्र में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन बेबी हैं। सचिन बेबी ने इस सत्र में 800 से भी अधिक रन बनाए हैं। सचिन ने केरल की ओर से खेलते हुए 12 पारियों में कुल 830 रन बनाए हैं। उनका उच्चतम स्कोर 131 रन का रहा था। वहीं औसत करीब 83 के आस पास का रहा है। इस सत्र में इस युवा ने 4 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए हैं। सत्र में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी चेतनेश्वर पुजारा हैं। पुजारा ने भी इस सत्र में 800 से अधिक रन बनाए, पुजारा ने सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए 13 पारियों में कुल 829 रन बनाए हैं। उनका सबसे अधिक स्कोर 234 नाबाद का रहा था। इसके साथ ही औसत करीब 70 के आस पास का रहा है। इस सत्र में उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाये हैं। वहीं सत्र में चौथे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी पन जगदीशन हैं। जगदीशन ने भी इस सत्र में 800 से भी अधिक रन बनाए, जगदीशन ने तमिलनाडु के लिए खेलते हुए 13 पारियों में कुल 816 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 321 रन और औसत करीब 74 के आस पास का रहा है। इस सत्र में उनके नाम 2 शतक और 1 अर्धशतक है। वहीं पांचवे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी शाश्वत रावत हैं। बड़ोदा के लिए खेलते हुए शाश्वत ने 13 इनिंग्स में कुल 784 रन बनाए। उनका शीर्ष स्कोर 207 रन का रहा था।

श्रीलंका ने 3 विकेट से जीता दूसरा वनडे

बांग्लादेश के खिलाफ पथुम निसांका का शतक सीरीज 1-1 से बराबर, डिसाइडर 18 मार्च को

मुम्बई। श्रीलंका ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 3 विकेट से हरा दिया। चट्टोग्राम में बांग्लादेश ने 7 विकेट पर 286 रन बनाए। श्रीलंका ने 47.1 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। श्रीलंका से ओपनर पथुम निसांका ने 114 रन बनाए और अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाया। दूसरे वनडे में जीत के साथ श्रीलंका ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे 18 मार्च को चट्टोग्राम में ही खेला जाएगा।

बांग्लादेश की शुरुआत खराब, लिट्टन पहले ओवर में आउट

जह्दुर अहमद चौधरी स्ट्रेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही, टीम ने पहले ही ओवर में लिट्टन दास का विकेट गंवा दिया। लिट्टन खाना भी नहीं खोल सके। उनके बाद सोम्य सरकार और कसान नजमुल हुसैन शांति ने टीम को 50 रन के पार पहुंचाया। शांति 40 रन बनाकर आउट हुए और उनकी सोम्य के साथ 75 रन का पार्टनरशिप टूटी। सरकार ने फिर तौहीद हदॉय के साथ फिफ्टी पार्टनरशिप की। वह 68 रन बनाकर आउट हुए और दोनों के बीच 55 रन की साझेदारी टूटी।

सेचुरी बनाने से चूके हदॉय

130 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिरने के बाद हदॉय एक एंड पर टिक गए। उनके सामने मुशाफिकुर रहम 25, मेहदी हसन मिराज 12 और तंजिम हसन



साकिब 18 रन बनाकर आउट हो गए। तस्कीन अहमद 10 बॉल में 18 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। उनके सामने हदॉय ने 102 बॉल पर 96 रन बनाए। उन्होंने पारी में 3 चौके और 5 सिक्स लगाए। टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाए।

हसरंगा को 4 विकेट

श्रीलंका के लिए लेग स्पिनर विनंद् हसरंगा ने 10 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट झटके। तेज गेंदबाज दिलशाण मदुरांका ने 30 रन देकर 2 विकेट लिए। वह 6.4 ओवर ही गेंदबाजी कर सके, उन्हें 7वें ओवर में बॉलिंग करने में दिक्कत हुई, जिस कारण जयिथ विलियामो ने उनका ओवर कम्प्लीट किया। श्रीलंका से एक सफलता प्रमोद मदुरांका को भी मिली।

श्रीलंका की भी शुरुआत खराब

287 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम की भी शुरुआत खराब रही। ओपनर अविष्का फर्नांडो खाना खोले बगैर पहले ही ओवर में आउट हो गए। उनके बाद कसान कुसल मेंडिस 16 और सदीरा समरविक्रमा भी एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम ने 43 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए।

असलंका और निसांका ने की सेचुरी पार्टनरशिप

पहले पावरप्ले में 3 विकेट गंवाने के बाद ओपनर पथुम निसांका और चरिथ असलंका ने संभलकर बैटिंग की। दोनों ने फिफ्टी पार्टनरशिप की और टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। दोनों ही प्लेयर्स ने अपनी-अपनी फिफ्टी पूरी कर

सेचुरी पार्टनरशिप की और स्कोर 150 रन के भी पार कर दिया।

निसांका का शतक, असलंका सेचुरी चूके

निसांका ने सेचुरी लगाई और टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। वह 114 रन बनाकर मेहदी हसन मिराज का शिकार हुए और दोनों के बीच 185 रन की साझेदारी टूटी। उनके बाद असलंका भी 91 रन बनाकर आउट हो गए। टीम ने 235 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए। आधी टीम पवेलियन लौटने के वक्त श्रीलंका को 12 ओवर में 52 रन ही चाहिए थे। तभी जयिथ विलियामो 9 और विनंद् हसरंगा 25 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि दुनिथ वेल्हाला ने 16 बॉल पर 9 रन बनाए और टीम को जीत के पार पहुंचा दिया।

शोरिफुल-तस्कीन को 2-2 विकेट

बांग्लादेश के लिए शोरिफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद ने 2-2 विकेट लिए। वहीं एक-एक सफलता तंजिम हसन साकिब, मेहदी हसन मिराज और तैजुल इस्लाम को भी मिली।

सीरीज डिसाइडर 18 मार्च को

दूसरे वनडे के नतीजे के बाद 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। तीसरा मैच 18 मार्च को चट्टोग्राम में ही खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेली जा रही है। टी-20 सीरीज श्रीलंका ने 2-1 से जीती थी। वहीं 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 22 मार्च से शुरू होगी।

एगिडी की जगह फ्रेजर मैकगर्क दिल्ली कैपिल्स की ओर से खेलेंगे

मुम्बई। दिल्ली कैपिल्स की टीम में शामिल दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एगिडी भी आईपीएल 2024 से बाहर हो गये हैं। ऐसे एगिडी की जगह पर दिल्ली ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेक फ्रेजर मैकगर्क को अपनी टीम में शामिल किया है। कैपिटल्स का अपना पहला मैच 23 मार्च को चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स से खेला है। फ्रेजर 29 गेंदों में शतक सबसे ध्यान में आए थे। उन्होंने कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है। आईपीएल की ओर से भी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली ने एगिडी की जगह फ्रेजर मैकगर्क को आईपीएल 2024 के लिए टीम में शामिल किया है। फ्रेजर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 एकदिवसीय मैच खेलें हैं। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख रूपए देकर टीम में शामिल किया है। यह उनका रिजर्व प्र्राइस था। इस क्रिकेटर का घरेलू मैचों में अच्छा रिकॉर्ड रहा है।



एगिडी फिट नहीं होने के कारण इस सत्र से बाहर हो गये हैं। की वजह से इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे, फ्रेजर ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 2 एकदिवसीय मैच खेलें हैं। उन्होंने 16 फर्स्ट क्लास मैचों में 550 रन बनाये हैं। उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है। फ्रेजर मैकगर्क ने लिस्ट ए में 21 मैच खेलें हैं। इस दौरान उन्होंने 525 रन बनाए हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में एक शतक और एक अर्धशतक भी है। फ्रेजर द मार्श कप में 29 गेंदों में शतक लगाकर चर्चा में आए थे। उन्होंने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मैच में 38 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन बनाए थे। यह मुकाबला तस्मानिया के खिलाफ अक्टूबर 2023 में खेला गया था। वहीं एगिडी ने कई मौकों पर शानदार गेंदबाजी की है। एगिडी ने आईपीएल में 14 मैच खेलकर 25 विकेट लिए हैं। उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है।

धोनी आईपीएल के बीच में ही छोड़ सकते हैं कप्तानी : रायडू

नई दिल्ली। पूर्व क्रिकेटर अंबाली रायडू ने कहा है चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के बीच में ही कप्तानी छोड़कर किसी अन्य खिलाड़ी को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। सीएसके के लिए पिछले सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रायडू का मानना है कि भविष्य को देखते हुए माही आर्षीपीएल के दौरान किसी युवा को चेन्नई का कप्तान बना सकते हैं। पिछले सत्र में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को सीएसके का कप्तान बनाया गया था पर लगातार असफल होने के कारण उन्होंने बीच में ही कप्तानी छोड़ दी थी। उसके बाद से ही ये जिम्मेदारी धोनी संभाल रहे हैं। उनकी कप्तानी में सीएसके को साल 2023 में पांचवीं बार खिताब मिला था। रायडू ने कहा, 'इंपैक्ट प्लेयर नियम के जरिए धोनी बीच के अवसरों में किसी और को कप्तानी सौंप सकते हैं।



राशिद खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया धमाकेदार कमबैक, 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ डाला

नई दिल्ली। राशिद खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की और आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राशिद खान ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 19 रन देकर तीनों विकेट झटके।

इसी के साथ राशिद खान ने एक नायाब उपलब्धि हासिल की। राशिद खान ने अफगानिस्तान के कप्तान के रूप में टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। राशिद खान ने नवरोज मंगल का रिकॉर्ड तोड़ा। राशिद खान से पहले अफगानिस्तान के कप्तान के रूप में टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड नवरोज मंगल के नाम दर्ज था। मंगल ने फरवरी 2010 में आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टी20 क्वालीफायर्स में 4 ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे। 14 साल के बाद राशिद खान इस रिकॉर्ड के बादशाह बन गए हैं।

- टी20 में अफगानिस्तान के कप्तान का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
- राशिद खान बनाम आयरलैंड - शारजाह (2024), 4-0-19-3।
 - नवरोज मंगल बनाम आयरलैंड - दुबई (2010), 4-0-23-4।
 - गुलबदीन नईब बनाम श्रीलंका - हांगकॉ (2023), 4-0-28-3।
 - मोहम्मद नबी बनाम स्कॉटलैंड - शारजाह (2013), 4-0-12-2।
 - मोहम्मद नबी बनाम श्रीलंका - दुबई (2022), 4-0-14-2।
 - राशिद खान की वापसी बेकार



बहरहाल, राशिद खान की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी अच्छी नहीं रही। अफगानिस्तान को आयरलैंड के हाथों पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 38 रन की शिकस्त सहनी पड़ी। तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में अफगानिस्तान की टीम 0-3 से पिछड़ गई है। शारजाह में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 149 रन बनाए। जबवा में अफगानिस्तान की टीम 18.4 ओवर में 111 रन पर ऑलआउट हो गई। दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।

राष्ट्रमंडल खेल विजेता लड़कियों के हॉस्टल में घुसा, शिविर से बाहर, वेटलिफ्टिंग महासंघ ने की कार्रवाई

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर को लड़कियों के हॉस्टल में घुसने पर पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के शिविर से निकाल दिया गया। एनआईएस पटियाला में बृहस्पतिवार रात को घटी घटना में इस वेटलिफ्टर को हॉस्टल के अंदर सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। हड़कंप मचने पर मामले की सूचना संस्थान के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक के साथ दिल्ली स्थित साई हेडक्वार्टर और भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ को दी गई। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए वेटलिफ्टर को तत्काल शिविर से निकालते हुए शुक्रवार को घर वापस भेज दिया गया।



खेलों में स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी बृहस्पतिवार की रात पीटी उषा गल्लू हॉस्टल में घुसा तो उसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और वीडियो बना लिया।

वेटलिफ्टिंग महासंघ ने की कार्रवाई

भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस तरह की अनुशासनहीनता बरदाश्त नहीं की जाएगी, इसी लिए खिलाड़ी को शिविर से निकाला गया है। यह पहला मामला नहीं है जब महासंघ ने किसी नामी वेटलिफ्टर को

सुरक्षा कर्मियों ने बनाया वीडियो

एनआईएस पटियाला में इस वक्त पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और महिला पहलवानों के शिविर चल रहे हैं। संस्थान में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के अलग-अलग हॉस्टल हैं। महिलाओं के हॉस्टल में पुरुष खिलाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। गेम्स रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रमंडल

वेटलिफ्टरों के क्वालिफिकेशन पर भी असर पड़ा है। अब पुरुषों में कोई भी भारतीय वेटलिफ्टर पेरिस ओलंपिक में नहीं खेल पाएगा। इस माह के अंत में थाईलैंड में होने वाले विश्वकप में सिर्फ मीराबाई चानू और बिंदिया रानी ही खेल पाएंगे और वहीं दोनों लिफ्टर पेरिस ओलंपिक में खेलने की दौड़ में बने रहेंगे।

पेरिस की दौड़ में गीरा, बिंदिया ही बचे

वेटलिफ्टर पर कार्रवाई से पेरिस ओलंपिक में

एसी खरीदते हुए बरतें सावधानी



गर्मी का सीजन आते ही एयर कंडीशनर की खरीदारी तेजी से शुरू हो जाती है। अगर आप भी एसी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप फायदे में रहें।

- 1) कितने टन का एसी: एसी कितने टन का लेना है, यह कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। अंतर हम एसी खरीदते हुए इस बात का

ध्यान नहीं रखते, फिर नतीजा यह होता है कि इससे कमरा पूरी तरह ठंडा नहीं हो पाता।

- 2) बिजली की बचत: एसी खरीदते समय एसी की स्टार रेटिंग चेक कर लें, इससे आपकी बिजली की बचत होगी।
- 3) ठंडक चारों तरफ: पहले जो एसी

आते थे, वे एक तरफ ही हवा फेंकते थे, जिससे पूरे कमरे में ठंडक काफी देर बाद होती थी लेकिन अब ऐसे एसी आते हैं, जिनकी फैन विंडो चारों तरफ घूमती है। इससे कमरे में जल्द ही ठंडक हो जाती है।

- 4) इसका भी रखें ध्यान: मार्केट में इन दिनों कम रेट के एसी भी अवेलेबल हैं, जिनका दाम सुनकर आप खुश हो सकते हैं लेकिन ये एसी बिजली काफी खींचते हैं।

स्वास्थ्य

शहद लगाएं, बालों को कोमल और खूबसूरत बनाएं



आप भी रूखे और बिखरे बालों की समस्या से परेशान हैं तो बालों को कोमल और सुलझा हुआ बनाने का राज आपके किचन में छिपा है। शुद्ध शहद प्राकृतिक कंडिशनर माना जाता है और इसे लगाने से बाल कोमल बनते हैं। शहद, बालों के माइश्र को बरकरार रखता है और उन्हें हेल्थी और खूबसूरत बनाता है।

शहद से धोएं बाल

एक मग पानी में एक कप शहद मिलाएं। बालों में शैप करने के बाद इस मिस को धीरे-धीरे बालों पर डालें। इस मिस को स्केल्प पर लगाकर उंगलियों से अच्छी तरह से मसाज करें और फिर पानी से धो लें। इससे आपके बाल सॉट और शाइनी हो जाएंगे।

हनी-ऑलिव ऑयल ट्रीटमेंट

2 चेमच ऑलिव ऑयल को गर्म करें और इसमें 2 चेमच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को मास्क की तरह बालों पर लगाएं। 10 मिनट तक इसे बालों पर लगा रहने दें और फिर शैप करें। ऐसा

करने से बालों को पोषण भी मिलेगा और बाल सॉट भी बनेंगे।

शहद-दही का मास्क

दही और शहद दोनों ही बालों को सॉट बनाने और उनका माइश्र बरकरार रखने का काम करते हैं। एक कप सादी बिना लेवर वाली दही में एक चौथाई कप शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर स्केल्प से लेथ तक बालों पर मास्क की तरह लगाएं और करीब 20 मिनट के लिए सूखने दें। 20 मिनट बाद बालों को धो लें।

दूध और शहद का पोषण

दूध और शहद का मिश्रण लगाने से डेजेन और रूखे बाल फिर से सही हो जाएंगे। आधा कप फुल फेटेड मिल्क में 2-3 चेमच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को हल्का गर्म करें ताकि शहद दूध में अच्छी तरह से घुल जाए। इस मिश्रण को सावधानी से बालों पर लगाएं और 20 मिनट बाद बालों को अच्छी तरह से धो लें।



अभी गर्मी का मौसम पूरे शबाब पर नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ता पारा आने वाली दिक्तों की दस्तक तो दे ही रहा है। गर्मी के मौसम को छकाने के लिए एयर कंडिशनर से बड़ा हथियार या हो सकता है। एसी से जुड़ी जरूरी जानकारी दे रहे हैं अमित

अगर गर्मी भगाने के लिए एसी लेने का प्लान बना रहे हैं तो मार्केट में आने वाले नए मॉडल्स पर नजर जरूर रखें। इससे आपको बेहतर कूलिंग वाले एसी तो मिलेंगे ही, साथ ही नई तकनीक का सहारा भी मिलेगा।

तया देखें नए मॉडल्स में

- मार्केट में आए एसी के नए मॉडल्स बिजली की खपत के लिहाज से काफी किफायती साबित हो सकते हैं।

- पारंपरिक विंडो और स्प्लिट के अलावा इनके बीच का भी एक वैरिएंट मार्केट में मौजूद है। इन्हें यूब एसी कहते हैं। यह एसी है तो विंडो, लेकिन उन कमरों के लिए कारगर है, जिनमें खिड़की नहीं है। इनका कूलिंग और कंट्रोलिंग हिस्सा कमरे के भीतर रहता है और गर्मी फेंकने वाला हिस्सा बाहर। यूब एसी 1.25 टन से 1.5 टन के ऑप्शन में मिलते हैं।

- मार्केट में इन्वर्टर एसी भी आ गए हैं। इनका मतलब यह कई नहीं है कि एसी इन्वर्टर से चलेंगे। यह खास तकनीक एसी में इस तरह का फंशन है, जो जरूरत के मुताबिक ही कंप्रेसर पर जोर डालता है। मिसाल के तौर पर अगर कूलिंग सेट तापमान तक पहुंच गई है तो कंप्रेसर में मौजूद मोटर अपनी रेटार कम कर देगा। इससे बिजली की खपत कम हो जाएगी। फिलहाल इस तरह की तकनीक केवल स्प्लिट एसी में ही मौजूद है।

- अगर आप कमरे की दीवारों का रंग-रोगन कराने वाले हैं तो प्लान करके मैचिंग कलर और डिजाइन में भी एसी खरीद सकते हैं।

ऐसा एसी भी बाजार में आया है, जो कूलिंग के साथ ही मच्छर भगाने का दावा भी करता है। अगर आप मच्छर से परेशान रहते हैं तो यह खरीद सकते हैं।

- कुछ एसी बरसात के मौसम के हिसाब से अलग मोड लेकर बाजार में आए हैं जो कूलिंग में इजाफा किए बिना ही माइश्र कंट्रोल करते हैं। इससे मौसम की चिपचिपी गर्मी से राहत मिलती है।

- मार्केट में अब ऑल वेदर एसी भी मौजूद हैं जो गर्मी में ठंडक के साथ ठंड में आपको गर्म भी रखेंगे।

- अब उन एसी की डिमांड लगातार बढ़ रही है जो कम पावर में बेहतर कूलिंग देते हैं। ऐसे में ज्यादा स्टार रेटिंग वाले एसी डिमांड में हैं।

- मार्केट में ज्यादा दिनों की ओटोर सेल सर्विस (2-5 साल) वाले एसी आ गए हैं, जो एसी खरीदने के बाद किसी भी परेशानी से आपको बचाते हैं।

कितना बड़ा एसी लें

- एसी को 1 स्क्वियर फुट जगह को ठंडा करने में 20 बीटीयू प्रति घंटा खर्च करना पड़ता है। बीटीयू का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 3.5 बीटीयू 1 घंटे के बराबर होता है। यह टन वजन वाला टन नहीं है, बल्कि एसी की क्षमता को नापने में इस्तेमाल होने वाली इकाई है।

- अगर इस गणित में न पड़ें तो हम कह सकते हैं कि 100 स्क्वियर फुट (10x10 फुट का कमरा) के कमरे के लिए 1 टन का एसी कारगर होगा। इस हिसाब से 100 से 150 स्क्वियर फुट (10x15 फुट का कमरा) की जगह को ठंडा रखने के लिए 1.5 टन का एसी काफी होगा। 200 स्क्वियर फुट या उससे

नए प्रेमी जोड़े अक्सर करते हैं ऐसी गलतियां

हर जगह हाथों में हाथ डालकर चलना, पॉलिक् प्लेस पर प्यार का इजहार करना, अपने अलावा पूरी दुनिया को भुला देना। नए-नए रिश्ते में बंधने वाले कपल्स अक्सर इस तरह की चीजें करते हैं जो दूसरों के लिए कष्टकारी और खीझ दिलाने वाला साबित हो सकता है-

1. सोशल मीडिया का असर

सोशल मीडिया के इस जमाने में जैसे ही किसी शेरस का रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल से इन लव होता है, तो इनमें से कई प्रेमी जोड़े ऐसे हैं जो तस्वीरें पोस्ट करने की गतिविधि शुरू कर देते हैं। थोड़ी-थोड़ी देर में अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी खलना, साथ-साथ कहां घूमने गए ये बताना... अपने प्यार का इजहार करने में कुछ गलत नहीं है लेकिन आपकी जरूरत से ज्यादा उत्सुकता दूसरों को परेशान कर सकती है।

2. दोस्तों से दूरी बनाना

अगर आप किसी नए रिश्ते में बंधे हैं तो जाहिर



सी बात है आप उस इंसान के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अपने प्रेमी या प्रेमिका को वक्त देने के लिए दोस्तों को भूल जाएं। आपके लाइफ में हर किसी की बराबर अहमियत

होनी चाहिए।

3. एक रंग के कपड़े पहनना

पहले-पहले प्यार में अंतर लोग अजीबोगरीब चीजें करते हैं। उदाहरण के लिए- मैचिंग कलर के

कपड़े पहनना। इसलिए अगली बार अगर आप किसी प्रेमी जोड़े को एक जैसे रंग के कपड़े पहने देखें तो उन्हें दोषी न ठहराएं। ये सब तो वे प्यार के लिए कर रहे हैं ना...

4. हमें सब पता है

आप इसे प्यार का घमंड कहें या कुछ और लेकिन जब दो लोग किसी नए रिश्ते में बंधते हैं तो अंतर वे दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें अचानक ऐसा लगने लगता है कि वे जीवन के ऐसे रहस्यपूर्ण मुकाम पर पहुंच गए जिसके बारे में समझना दूसरों के लिए संभव नहीं है।

5. जरूरत से ज्यादा बोलना

कुछ लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि दुनिया के सभी लोग उनके पार्टनर से आसक्त नहीं हैं और ऐसे लोग अक्सर दूसरों को अपने पार्टनर के बारे में बातें बता बतकर पका देते हैं।

रेसिपी



विधि

मूंग और 3 कप पानी को एक प्रेशर कुकर में मिलाकर, 3 सिटी के लिए प्रेशर कुक कर लें। ढक्कन खोलने से पूर्व सारी भाप निकलने दें। पानी छाने नहीं। हेन्ड ब्लेन्डर का प्रयोग कर मूंग को पीसकर मुलायम मिश्रण बना लें। एक तरफ रख दें। एक गहरे नॉन-स्टिक पैन में तेल गरम करें और जीरा डालें। जब बीज चटकने लगे, हींग, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर मध्यम आंच पर कुछ सेकेंड तक भुन लें। पीसे हुए मूंग का मिश्रण, नमक और 1 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर, बीच-बीच में हिलाते हुए 4-5 मिनट के लिए पका लें। नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। धनिया के पत्ते से सजाकर गरमा गरम परोसें।

मूंग सूप

सामग्री

1/2 कप मूंग, 8 घंटे के लिए भिगोकर छानी हुई, 1 टी-स्पून तेल, 1/2 टी-स्पून जीरा, 1/4 टी-स्पून हींग, 1/2 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4-5 कड़ी पत्ता, नमक स्वादअनुसार, 2 टी-स्पून नींबू का रस, सजाने के लिए: धनिया का पत्ता

शिशु के कान में जमी मैल को इन 4 तरीकों से करें साफ



जन्म के बाद शिशु को याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। खासकर, उसकी साफ-सफाई पर तो ज्यादा ध्यान देना पड़ता है यॉकि छोटे बच्चे बहुत जल्द संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में अगर उनके कान की बात की जाए तो छोटे बच्चों के कान में मैल बहुत जल्दी जम जाती है जिन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप अपने शिशु के कान की सफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं।

1. नहाने के बाद करें

जब भी आप बच्चों को नहलाएं तो नहलाने के बाद आप उनके कान की सफाई करना ना भूलें। नहलाने के बाद बच्चों के कान से मैल आसानी से निकल जाती है यॉकि इस समय कान ज्यादा सूखे नहीं होते हैं और न ही बच्चे को तकलीफ होती है।

2. बेबी इयर बड से करें साफ

शिशु के कान साफ करते समय हमेशा बेबी

इयर बडका ही इस्तेमाल करें। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि इयर बड कान के ज्यादा अंदर तक ना डालें यॉकि ज्यादा गहराई तक डालने से कान के पर्दे में चोट लगने का खतरा रहता है।

3. जैतून का तेल

शिशु का कान आप जैतून तेल की मदद से भी साफ कर सकते हैं। कानों में जैतून के तेल की 3 से 4 बूँद डालें और इसके बाद रातभर के लिए छोड़ दें। यह तेल कानों के अंदर रात भर काम करेगा और सुबह होने तक कान की सारी मैल नॉन होकर बाहर आ जाएगी।

4. सोते समय करें सफाई

बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उनका शरीर कभी भी शांत नहीं रहता है। ऐसे में कोशिश करें कि जब बच्चे सो रहे हों तब उनके कानों की सफाई करें यॉकि जब बच्चे के जगो हूए में कानों की सफाई करते हैं तो उससे कानों में चोट लगने का खतरा बना रहता है।



विधि

दालों को धोकर, 11/2 कप पानी मिलाकर, 3 सिटी तक प्रेशर कुक कर लें। ढक्कन खोलने से पूर्व सारी भाप निकलने दें। एक तरफ रख दें। एक गहरे नॉन-स्टिक पैन में तेल गरम करें और जीरा, लौंग, तेजपत्ता, लाल मिर्च और हींग डालें। जब बीज चटकने लगे, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट डालकर कुछ सेकेंड तक भुन लें। पकी हुई दाल, हल्दी पाउडर, नींबू का रस, नमक और 11/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। उबाल लाकर, 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर, बिच मे एक बार हिलाते हुए उबाल लें। धनिया से सजाकर, भाखरी और लहसुन की चटनी के साथ गरमा गरम परोसें।

त्रेवटी दाल

सामग्री

1/4 कप चना दाल, 1/4 कप तुवर दाल, 1/4 कप पीली मूंग दाल, 2 टैबल-स्पून तेल, 1/2 टी-स्पून जीरा, 2 लौंग, 1 तेजपत्ता, 1 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, टुकड़ों में तोड़ी हुई, 1/4 टी-स्पून हींग, 2 टी-स्पून अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 टी-स्पून हल्दी पाउडर, 1 टैबल-स्पून नींबू का रस, नमक स्वादअनुसार, सजाने के लिए: 2 टैबल-स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, परोसने के लिए: भाखरी, लहसुन की चटनी